●वर्ष-5
●अंक-161
रायपुर, गुरुवार
19 फरवरी 2026
●पृष्ठ-8
●मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› पर्यटन मंत्री वीर बुधु भगत ...

शोधार्थी संवादः सीएम योगी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से की मुलाकात, 30 मिनट तक हुई दोनों के बीच बातचीत

विश्व गुरु बनना है तो सत्य के पीछे शक्ति लानी होगी

लखनऊ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित शोधार्थी संवाद में कहा कि वैश्वीकरण का मतलब बाजारीकरण से है, जो खतरनाक है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब तक सब सुखी नहीं होंगे, एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। जीवन उपभोगवादी नहीं होना चाहिए।

कहा कि पश्चिमी देशों ने जड़वाद फैलाया। उनकी सोच है कि बलशाली बनकर खुद जियो और बाकी को छोड़ दो। जो बाधक बने, उन्हें मिटा दो। यही काम आज अमेरिका, चीन कर रहे हैं। कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में शक्तिशाली होना पड़ेगा। दुनिया तभी मानती है जब सत्य के पीछे शक्ति हो।

दूसरे सत्र में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रमुख जन संवाद में विचार व्यक्त किया। उधर, देर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज पहुंचकर लगभग आधे घंटे तक भागवत से बातचीत की। सरसंघचालक ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसाय नहीं हो सकते। यह सबके लिए सुलभ होने चाहिए। पश्चिम के लोगों ने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया। हमारी शिक्षा व्यवस्था हटाकर अपनी थोपी जिससे उन्हें काम करने के लिए काले अंग्रेज मिल जाएं। जो बिगाड़ा उसको ठीक करना होगा। मैं और मेरा परिवार ही सब कुछ है, यह न सोचकर पूरे देश के लिए सोचना होगा। संघ किसी के विरोध में नहीं है। संघ को लोकप्रियता, प्रभाव और शक्ति नहीं चाहिए। संघ को पढ़कर नहीं समझा जा सकता है। संघ को अंदर आकर समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की दिशा और दशा बदलने में शोध की बड़ी भूमिका है।सत्यपरक बातें सामने आनी चाहिए। अज्ञानता से हम भारत को समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रामाणिकता के साथ शोध करने और निःस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने की सीख दी। कहा कि संघ को लेकर बहुत दुष्प्रचार होता है। शोधार्थियों को सत्य सामने लाना चाहिए। सृष्टि जिन नियमों से चलती है, वह धर्म है। धूल का एक भी कण धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्म बताता है कि हमें अकेले नहीं सबके साथ जीना है। संघ प्रमुख ने पर्यावरण के प्रति मित्र भाव से रहने की सीख दी।

स्पेन और फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष से मिले प्रधानमंत्री मोदी

भारत-यूरोप एफटीए से सुनहरे युग की शुरुआत

नई दिल्ली। 2026 को भारत और स्पेन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और एआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोदी ने बताया कि इस दौरान भारतीय और स्पेनिश विश्वविद्यालयों की बड़ी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगी, जो लोगों को जोड़ने में मदद करेगी।

भारत-यूरोप संबंध पर क्या बोले पीएम मोदीः इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूरोपीय एफटीए से भारत और स्पेन के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों के लिए नए अवसर खुलेंगे। दोनों नेताओं ने टाटा-एयरबस सहयोग के तहत सी-295 परिवहन विमान की अंतिम असेंबली लाइन की सफलता का भी स्वागत किया। उन्होंने भारत-स्पेन डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने सह-निर्माण और सह-उत्पादन आधारित रक्षा सहयोग को भी भविष्य की दिशा बताया।

बता दें कि स्पेन के राष्टपति इस आधिकारिक दौरे पर 18 से 19 फरवरी तक भारत में हैं। सांचेज ने समिट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके परिणाम वैश्विक एआई गवर्नेंस को आकार देने में मदद करेंगे। उन्होंने शिक्षा में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की, खासकर भारत की नई शिक्षा नीति के तहत।पीएम मोदी और सांचेज के बीच बैठकः पीएम मोदी और सांचेज ने पर्यटन, व्यापार, निवेश, तकनीक, नवाचार, जलवायु और नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने स्पेनिश विश्वविद्यालयों और संस्थानों को एसटीईएम और तकनीकी क्षेत्रों में भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग, और स्पेन के भारत-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने की बात पर भी चर्चा की।फिनलैंड के पीएम के साथ बैठक में क्या-क्या ?: इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ भी बैठक की। उन्होंने एफटीए के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत-फिनलैंड व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं।

राज्यसभा की दो सीटों के लिए 16 मार्च को होगा मतदान

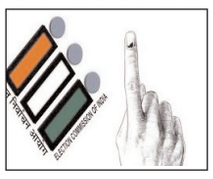

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज अप्रैल-2026 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों की रिक्त सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके माध्यम से देश के 10 राज्यों में कुल 37 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा।छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से 2 सदस्यों, श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी और सुश्री फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को पूर्ण हो रहा है। इन दोनों सीटों के रिक्त होने के कारण निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम-निर्देशन पत्र 5 मार्च तक दाखिल किये जा सकेंगे। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 16 मार्च को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा तथा उसी दिन सायं 5 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी।संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी। राज्यसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी अपना नाम-निर्देशन पत्र 26 फरवरी से 5 मार्च तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में निर्धारित स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर (संचालक, छत्तीसगढ़ विधानसभा) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन में राज्य के कुल 90 विधानसभा सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 54, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सदस्य शामिल हैं। सभी विधायक मतपत्र के माध्यम से मतपेटी में अपना मत प्रदान करेंगे। मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए बैंगनी रंग के स्केच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जाएगी। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपादित की जाएगी। अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक ';' में पृथक रूप से संलग्न है।

रायपुर। मुख्यमंत्री ी विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा की पूज्य माता स्वर्गीय श्रीमती कुसुम सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी

नईदिल्ली। सरकार छोटे बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों से बातचीत कर रही है। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। वैष्णव ने एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि अब कई देश इस बात को मान रहे हैं कि सोशल मीडिया के इस्तोमल के लिए उम्र आधारित विनियमन होना चाहिए। यह हमारे डिजिटल व्य ?क्तिगत डेटा सुरक्षा यानी डीपीडीपी अधिनियम का हिस्सा था

और उसी दौरान हमने युवाओं के लिए उपलब्ध सामग्री का वर्गीकरण उम्र के आधार पर किया था।मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार एक निश्चित उम्र से छोटे बच्चों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध पर विचार करने के अलावा डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिए बेहतरीन समाधानों पर भी मध्यस्थों के साथ चर्चा कर रही है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी अपने राज्य में इस नियम को लागू करने का संकेत दिया।

प्रमुख समाचार

पीएम मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का करेंगे उद्घाटन

दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का दौरा करेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार की सुबह लगभग 9ः40 बजे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ-साथ फ्रांस के राष्टपति, संयुक्त राष्ट के महासचिव और विश्वभर के विभिन्न शीर्ष उद्योगपति भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अन्य नेताओं के साथ सुबह लगभग 11 बजे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का दौरा करेंगे, जहां वे विभिन्न देशों के पवेलियन का अवलोकन करेंगे।

इसके बाद, पीएम मोदी दोपहर लगभग 12 बजे से आरंभ होने वाले नेताओं के पूर्ण सत्र में भाग लेंगे। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बहुपक्षीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि एक साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसमें शासन, अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। इसके बाद, शाम 5.30 बजे से सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें वैश्विक प्रौद्योगिकी और उद्योग जगत की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी सरकारी नेतृत्व के साथ मिलकर निवेश, अनुसंधान सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला और एआई प्रणालियों की तैनाती पर चर्चा करेंगे।

राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से मिलाया हाथ, हुई बातचीत

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक निवास नंदनवन में मुलाकात की। यह बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनावों के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने बातचीत थी। जिसमें दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक सूत्र ने कहा कि

दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। राज ठाकरे ने नंदनवन में शिंदे से मुलाकात के दौरान बंगले में किए गए सुधारों की सराहना की और मुंबई के पुराने विरासत भवनों की फोटो फ्रेम्स का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।गौरतलब है कि मनसे ने कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र में शिंदे की शिवसेना का समर्थन किया था। शिंदे ने पिछले महीने राज ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ को कभी नहीं देखा और हमेशा व्यापक दृष्टिकोण से निर्णय लिए। उन्होंने कहा राज ठाकरे ने पीएम मोदी का भी समर्थन किया और विधानसभा चुनावों में भी हमारा साथ दिया।

विशाखापत्तनम में खुलेगा गुगल का बड़ा एआई डेटा सेंटर

नई दिल्ली। गूगल ने देश में अपने एआई फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के एक नए राउंड की घोषणा की है, जो विशाखापत्तनम में एआई हब बनाने के अपने पहले अनाउंस्ड 15 बिलियन डॉलर के प्लान में शामिल है। गूगल ने घोषणा की कि डीपमाइंड साइंटिफिक रिसर्च को तेज करने के लिए भारतीय सरकारी एजेंसियों और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ काम करना शामिल है, जो रिसर्चर्स को साइंस के लिए लेटेस्ट एआई मॉडल्स के साथ-साथ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और मेंटरशिप प्रोग्राम्स तक एक्सेस देगा, जिनका मकसद स्टूडेंट्स और शुरुआती करियर वाले साइंटिस्ट्स की स्किल्स को बढ़ाना है।गूगल ने क्लासरूम में जेनरेटिव ट्रू टूल्स को इंटीग्रेट करने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ भी पार्टनरशिप की है।

कैबिनेट मीटिंगः मॉब कल्चर बर्दाश्त नहीं : तारिक रहमान

ढाका। बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना, कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाना तथा बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में किसी तरह की समस्या न होने देना सरकार की प्राथमिकता है.

बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है. प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में बुधवार को नई कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट के सदस्य और सलाहकार शामिल हुए. बैठक में सरकार ने शुरुआती तौर पर तीन प्रमुख प्राथमिकताएं तय कीं और उन्हें लागू करने का निर्णय लिया.इन तीन प्राथमिकताओं में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार और बिजली व ऊर्जा की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है. बैठक दोपहर करीब तीन बजे प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में शुरू हुई. इसके बाद प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ भी अलग से बैठक की।

प्रियंका गांधी ने संभाली असम चुनाव की कमान

नईदिल्ली। कांग्रेस ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम दौरे पर पहुंचेंगी और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि, कांग्रेस सांसद प्रियंका

गांधी असम में दो दिनों का दौरा करेंगी, जहां वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर चुनाव की रणनीति पर महत्वपूर्ण बैठकें करेंगी। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भाजपा में शामिल होने का एलान कर दिया है।प्रियंका गांधी वाड्रा असम कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारी, फ्रंटल संगठन के नेता, पार्टी के विभिन्न विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगी। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि पिछली बार गुटबाजी और समन्वय की कमी से पार्टी को नुकसान हुआ।

महाशक्ति के रूप में उभरता डिजिटल भारत

प्रभात सिन्हा

नयी दिल्ली स्थित भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में 16 से 20 फरवरी तक संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा 'इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट, 2026' केवल एक तकनीकी सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत की उस बदलती पहचान का प्रतीक है, जिसमें हमारा देश तकनीक के उपभोक्ता से निर्माता बनने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ अग्रसर हो रहा है। इस शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 300 से अधिक प्रदर्शनकर्ता, प्रसिद्ध वैश्विक तकनीकी नेताओं, सैकड़ों स्टार्टअप और हजारों शोधकर्ताओं व नीति विशेषज्ञों की मौजूदगी है।

यह आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2030 तक एआइ से लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर का योगदान होने का अनुमान है। भारत इस परिवर्तन का केवल दर्शक नहीं, बल्कि उसका सक्रिय भागीदार और संभावित नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रहा है। यह सम्मेलन भारत की उस तैयारी और दृष्टि का प्रमाण है, जो उसे डिजिटल युग की अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रही है।

इस शिखर सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें भाग लेने वाली वैश्विक हस्तियों की उपस्थिति है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एनवीडिया और अन्य अग्रणी तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी तथा एआइ शोधकर्ता इस मंच पर अपने विचार साझा कर रहे हैं।

सम्मेलन में इन वैश्विक नेताओं की सक्रिय भागीदारी दर्शाती है कि भारत अब तकनीक का रणनीतिक साझेदार और भविष्य का केंद्र बन चुका है। इस प्रकार के मंच भारत को वैश्विक तकनीकी नीतियों और निवेश के केंद्र में स्थापित करते हैं और देश की तकनीकी साख को और मजबूत बनाते हैं। भारत की डिजिटल शक्ति का आधार उसकी मजबूत और व्यापक डिजिटल अवसंरचना है। आज देश में 138 करोड़ से अधिक आधार पहचान जारी हो चुकी हैं, जिसने लगभग पूरी आबादी को डिजिटल रूप से जोड़ दिया है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2025 में यूपीआइ के माध्यम से 180 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किये गये,

जो दुनिया में सबसे अधिक हैं।

रोज करीब 70 करोड़ डिजिटल भुगतान यह दर्शाते हैं कि तकनीक अब भारत में केवल सुविधा नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी है। वर्ष 2014 में जहां केवल 25 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 85 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह परिवर्तन तकनीकी विस्तार के साथ सामाजिक सशक्तीकरण की एक नयी कहानी है। तेजी से विस्तार कर रही भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान देश की जीडीपी का करीब 12 फीसदी है।

आने वाले वर्षों में इसके 20 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। देश का एआइ बाजार भी तेज गति से बढ़ रहा है और 2032 तक इसके 130 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना है। नीति आयोग के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 500 अरब डॉलर से अधिक का योगदान कर सकती है। यानी एआइ भारत की आर्थिक शक्ति का नया आधार बन रहा है। इस सम्मेलन से देश में निवेश, अनुसंधान और नवाचार को नयी गति मिलेगी।

अभी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं और 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्थापित हो चुके हैं। एआइ और डीप-टेक क्षेत्र में निवेश चूंकि लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा ऐसे वैश्विक आयोजन देश में नये डाटा सेंटर, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और नवाचार केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे। इससे रोजगार के हजारों नये अवसर सृजित होंगे और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। एआइ का लाभ आज समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है।

देश के 14 करोड़ से अधिक किसान अब एआइ आधारित तकनीकों के माध्यम से मौसम और फसल से संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआइ आधारित तकनीक गंभीर बीमारियों का प्रारंभिक चरण में पता लगाने में सहायक हो रही है।

कुरूद कृषि महाविद्यालय में मोरिंगा आधारित परियोजना स्वीकृत

धमतरी। जिले के किसानों की आय वृद्धि एवं पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर द्वारा मोरिंगा (सहजन) की खेती, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि विषयक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कुरूद में संचालित होगी, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध है। परियोजना का नेतृत्व सहायक प्राध्यापक डॉ. पीयूष प्रधान (प्रधान अन्वेषक) द्वारा किया जाएगा। एक वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना का क्रियान्वयन प्रौद्योगिकी ग्राम केंद्र सिर्री (जिला धमतरी) एवं प्रौद्योगिकी ग्राम केंद्र रामपुर (जिला कबीरधाम) में किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 50 किसानों को प्रशिक्षण देकर प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत किसानों को मोरिंगा की उन्नत उत्पादन तकनीक, नर्सरी प्रबंधन, वैज्ञानिक कटाई एवं भंडारण पद्धतियों तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्माण संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मोरिंगा से तैयार पाउडर, न्यूट्रीशन सप्लीमेंट, चाय, खाद्य पूरक एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों की जानकारी देकर किसानों को अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराने की योजना है। मोरिंगा को चमत्कारी पौधा कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम एवं विटामिन पाए जाते हैं। कम लागत और न्यून जोखिम वाली यह फसल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच किसानों के लिए टिकाऊ विकल्प सिद्ध हो सकती है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण उन्मूलन, महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी तथा युवाओं के लिए सूक्ष्म उद्यमिता के अवसरों को भी बढ़ावा देगी। परियोजना का संचालन महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. नवनीत राणा के मार्गदर्शन में किया जाएगा। परिषद द्वारा इस हेतु लगभग 4.95 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें प्रशिक्षण, संसाधन व्यक्तियों का मानदेय एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। यह परियोजना पारंपरिक फसलों के साथ वैकल्पिक उच्च आय वाली फसल को बढ़ावा देकर जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी तथा पोषण वाटिका और स्थानीय स्तर पर पोषण आहार उपलब्धता को सुदृढ़ करेगी। इसी क्रम में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कुरूद के प्रोफेसर डॉ. ए. कुरैशी को उनके अभिनव कृषि उपकरण के लिए भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन पेटेंट प्रदान किया गया है।

18 दिवसीय स्वरोजगार उद्यम विकास कार्यक्रम का सफल आयोजन

सूरजपुर। शिवनंदनपुर, बिश्रामपुर में क्लस्टर भवन शिवनंदनपुर में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) छत्तीसगढ़ द्वारा 18 दिवसीय स्वरोजगार उद्यम विकास कार्यक्रम (एसईडीपी) का सफल आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों के लिए तैयार करना था। 18 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को उद्यमिता विकास, व्यवसाय योजना निर्माण, विपणन रणनीतियाँ, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टी. टीग्गा (जनरल मैनेजर) रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उद्यमिता को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

यह पहल मुख्यमंत्री के विकसित छत्तीसगढ़ के विज़न को साकार करने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाकर मेक इन इंडिया पहल को गति देने हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

वहीं ईडीआईआई के महानिर्देशक डॉ. सुनील शुक्ला युवाओं को उद्यमिता को एक सशक्त करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम ईडीसी छत्तीसगढ़ टीम, डॉ. अमित कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में, राज्य में एमएसएमई विकास हेतु एक सुदृढ़ एवं सतत उद्यमी पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

महुआ शराब बनाने वालों पर एक्शन, बलौदा बाजार आबकारी विभाग ने दी चेतावनी

- **आबकारी विभाग ने 1 लाख 70 हजार की अवैध शराब और 2550 किलो लाहन जब्त किया.**

बलौदा बाजार। अवैध तरीके से महुआ शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीते मंगलवार को एक बार फिर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख 70 हजार की अवैध शराब और महुआ लहान को जब्त किया। यह पूरी कार्रवाई आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश पर की गई। कलेक्टर दीपक सोनी और जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल ने भी कार्रवाई की मॉनिटरिंग की।

दरअसल, आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि कसडोल अंतर्गत ग्राम घटमड़वा डेरा, थाना गिधौरी क्षेत्र में अवैध महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। सूचना मिलते ही टीम ने योजनाबद्ध तरीके से मौके पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान नाला किनारे लावारिस हालत में भारी मात्रा में महुआ लाहन और तैयार महुआ शराब बरामद की गई। विधिवत तलाशी लेने पर 30 किलोग्राम क्षमता वाली प्लास्टिक बोरियों में भरी कुल 85 नग महुआ लाहन बरामद हुई, जिनका कुल वजन 2550 किलोग्राम था। इतनी बड़ी मात्रा में लाहन मिलना इस बात का संकेत है कि यहां बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण की तैयारी चल रही थी।

लाहन के अलावा मौके से 55 लीटर तैयार महुआ शराब भी जब्त की गई। कच्ची और खतरनाक शराब को प्लास्टिक के बड़े बड़े गैलेन में भरकर रखा गया था। जब्त कच्ची शराब और महुआ लहान की अनुमानित कीमत 1 लाख 70 हजार के करीब बताई जा रही है। जब्त किए गए सामान को मौके पर भी नष्ट कर दिया गया।

मौके पर कोई आरोपी मौजूद नहीं मिला, जिसके चलते अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)(क), 34 (1)(च), 34(2) और 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विभाग द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि आसपास के गांवों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

कसडोल के अर्जुनी भी आबकारी विभाग की टीम ने महुआ शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश दी। विभाग ने यहां से 30 लीटर शराब सहित कई सामान बरामद किया। आबकारी विभाग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। इस पूरी कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, आबकारी उप निरीक्षक मनराखन नेताम तथा नगर सैनिक कमल वर्मा और राजकुमारी पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

धान उठाव धीमा, खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक स्टॉक से समिति की चिंता बढ़ी

गरियाबंद। जिले में समर्थन मूल्य पर इस साल 50 लाख 65 हजार 726 क्विंटल धान खरीदी हुई, जिसमें से अब तक 28 लाख 25 हजार 888 क्विंटल ही परिवहन हो सका है। जिले में अब तक केवल 56.45 प्रतिशत धान का उठाव हो पाया है, जो पिछले दो साल की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत कम है। हालांकि प्रदेश के 33 जिलों में गरियाबंद की रैंकिंग उठाव के मामले में 15वें नंबर पर है। लेकिन देरी को देखते हुए समिति की चिंता बढ़ गई है। लगातार ब्रांच स्तर से जिले को पत्राचार कर समिति ने बफर लिमिट से कई गुना ज्यादा मात्रा फड़ो में मौजूद रहने से रखरखाव पर अतिरिक्त व्यय के अलावा धान के सुखने को लेकर चिंता जाहिर की है। क्योंकि खरीदी मात्रा से वजन घटा तो खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी मान, खरीदी में मिलने वाले कमीशन में कटौती के अलावा उन्हें अंतर की राशि भरपाई के लिए उन पर कानूनी

कार्रवाई अपनाई जाती है। मिलर्स में रुचि घटी ङ्क जिले में कुल 57 राइस मिल मौजूद हैं, जिनमें से इस बार केवल 45 मिलर्स के लिए डीओ जारी हो रहा है। आंकड़ों पर नजर डाले तो अब तक पिछले 1 माह में 21 लाख 17650 क्विंटल मात्रा राइस मिल्स के लिए जारी किया गया है, जबकि मिलर्स ने अब तक महज 13 लाख 73110 क्विंटल ही उठाव किया है। जिन्हें डीओ जारी किया गया है, उनके पास दो साल पहले का भी स्टॉक मौजूद है। एफसीआई में चावल रखने की जगह कम पड़ गई, इसके अलावा करोड़ों रुपए का बैंक गारंटी भी मिलर्स का फंसा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उदंती-सीता नदी अभ्यारण्य इलाके में 5 फरवरी से भारी मालवाहकों की आवाजाही नेशनल हाईवे में बंद कर दी गई है। शाम ढलने के बाद आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध से पहले रोजाना 150 ट्रक संग्रहण केंद्र कुंडेल पहुंचा करती थी, जिसकी संख्या आधी हो गई है। हालांकि प्रतिबंध के दायरे में 90 में से केवल 31 खरीदी केंद्र आते हैं। परिवहन कर्ताओं की लापरवाही के कारण अन्य स्थानों में भी उठाव प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख 98,840 क्विंटल का टीओ जारी किया गया है, जिसके एवज में ट्रांसपोर्टर केवल 13 लाख 74 हजार क्विंटल का उठाव कर पाए हैं। पिछले दो सालों से खरीदी में अनियमितता को लेकर चर्चित दीवानमुड़ा खरीदी केंद्र में अब तक सबसे कम उठाव होना कई संदेहों को जन्म देता है। ओडिशा सीमा से लगे इस केंद्र में 10 लाख 3519 क्विंटल की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। अब तक यहां से 39,460 क्विंटल परिवहन किया गया है, जबकि 10,800 क्विंटल क्षमता वाले खरीदी केंद्र में 64,5920 क्विंटल शेष है। उड़ीसा सीमा से लगे प्राय: सभी केंद्रों में तय बफर लिमिट से कई गुना ज्यादा धान की मात्रा मौजूद है। ऐसे में खरीदी के बाद किए जाने वाले भौतिक सत्यापन की सत्यता पर भी कई सवाल उठते हैं। मामले में मार्कफेड डीएमओ किशोर चंद्र ने कहा कि सभी केंद्रों के लिए पर्याप्त टीओ-डीओ जारी हुए हैं। सड़क में प्रतिबंध और मिलरो की संख्या कम होने के कारण उठाव में गति नहीं आ पा रही है।

करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी गया जेल

दुर्ग। राष्ट्रीय पेंशन योजना के खातों में फर्जी मृत्यु का दावा कर करोड़ों रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस फर्जीवाड़ा में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। यह मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। दअरसल, एचडीएफसी बैंक के बोकारो झारखंड के प्रबंधक ने दुर्ग के पाटन थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था की राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित खातों में फर्जी मृत्यु का दावा प्रस्तुत कर लगभग एक करोड़ 19 लाख रुपये की राशि फर्जी तरीके से निकाली ली गई है।

इसके बाद जब दुर्ग पुलिस ने जांच शुरू कि तो पता चला कि संबंधित व्यक्ति जीवित पाए गए। यानी कि जीवित व्यक्तियों को कागजों में मृत दर्शाया गया और फिर फर्जी मृत्यु दावा प्रस्तुत कर राशि निकाली गई।

तो वहीं राजेश कन्नौजिया नामक व्यक्ति दुर्ग में एक ऑनलाइन सेवा केंद्र को संचालित करता है। उसके द्वारा ग्राहकों से आधार, पैन कार्ड, बैंक संबंधी जानकारी प्राप्त कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर दावा प्रस्तुत किया जाता था। इनमें ज्यादातर सेवानिवृत्त कर्मचारी होते थे। इन दावों में पते असामान्य, अमान्य क्कककोड, बैंक खातों के लेन-देन में अनियमितता पाई गई। इस प्रकरण में ।ष्ठस्नष्ट लाइफ के पूर्व कर्मचारी राजेश ठाकुर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर जाली दस्तावेज अपलोड किया जाता था। उसके द्वारा गलत सत्यापन किया जाता था।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कौशल विकास प्लेसमेंट कैंप में 980 पदों पर हुई भर्ती

कोंडागांव। युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर आया है। जिला प्रशासन कोंडागांव द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 18 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप के माध्यम से कुल 980 रिक्त पदों पर भर्ती की हई। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजक द्वारा निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्रदान कर नियोजन किया गया। कैंप में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहकर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया, जिसमें एलएंडटी द्वारा निर्माण परियोजनाओं के लिए बढ़ई के 50 पद, राजमिस्त्री के 50 पद, बार बेंडिंग के 50 पद एवं स्टील फिक्सिंग के 50 पद, इलेक्ट्रिकल के लिए 50 के लिए भर्ती की हई। कार्य स्थल पनवेल मुंबई निर्धारित है और न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। प्रशिक्षण उपरांत 16 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन, साथ ही आवास उपलब्ध कराए गये।

दुर्ग में धर्म परिवर्तन के लिए मां पर दबाव बनाने का आरोप

दुर्ग। जिले में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े एक संवेदनशील मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला थाना नेवई क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने ही बेटे पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता महिला रिसाली भिलाई की रहने वाली हैं, उसने थाना नेवई में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उनका पुत्र उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज की, घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने यह भी बताया कि घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंक दिया गया और उनके पूजा-पाठ में बाधा डाली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298 और 299 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

बीमार भालू का रेस्क्यू कर कर किया गया इलाज

एमसीबी। कटते जंगल और बढ़ती आबादी का सबसे बुरा असर जंगली जानवरों पर पड़ रहा है। जंगल में खाने और पानी की कमी के चलते, अक्सर जंगली जानवर रिहायशी इलाके का रुख करने को मजबूर होते हैं। खड़गवां इलाके में एक भालू आए दिन रिहायशी बस्ती का रुख कर रहा था। गांव वाले बताते हैं कि भालू आए दिन बस्ती के आस पास घूमते दिखाई दे जाता था।स्थानीय लोगों ने बताया कि भालू बीमार है। इस वजह से उसमें फुर्ती की भी कमी है। बीमार होने की वजह खाना और पानी का नहीं मिलना है। स्थानीय लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भालू का सही से इलाज हो इसके लिए वन विभाग की टीम को बुलाया जाए। रेस्क्यू के साथ साथ भालू का सही इलाज भी इसके लिए पशु विभाग की भी मदद ली जाए। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग और पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पहले घेराबंदी कर भालू को पकड़ा गया,फिर भालू को जरुरी उपचार दिया गया। दवा देने के बाद भालू को वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर गई।

जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार फर्जी साइन से राशि आहरण

सूरजपुर। सूरजपुर जिले में जी राम जी योजना के काम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस भ्रष्टाचार की शिकायत जिम्मेदारों से की गई,जिसमें जांच के बाद आरोप सत्य पाए गए। सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक में ग्रामीणों की शिकायत पर हुई जांच में फर्जी हाजिरी का मामला सामने आया है।फिर भी ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की गंभीर जांच के बजाय सिर्फ लीपापोती की जा रही है।ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्टाचार का पूरा खेल जनपद से चल रहा है। सूरजपुर जिले के भैयाथान जनपद पंचायत अंतर्गत भैयाथान ग्राम पंचायत में लगभग 10 लाख रुपए लागत से मनरेगा के तहत काम हुआ था। इस काम में नाला जीर्णोद्धार कार्य में लगे मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। इसे लेकर ग्रामीणों ने 13 लोगों की फर्जी हाजिरी भरने का आरोप पंचायत कर्मचारियों पर लगाया था।इन आरोपों को लेकर जनपद स्तर पर जांच भी कराई गई, जहां चार-पांच लोगों की फर्जी हाजिरी भरे जाने का मामला उजागर हुआ।

जांजगीर चांपा में बंद राइस मिल पर वन विभाग का छापा

जांजगीर चांपा। नवागढ़ थाना इलाके में बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी की तस्करी का खुलासा वन विभाग ने किया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भादा स्थित एक बंद राइस मिल परिसर में रेड किया। रेड के दौरान टीम को मौके से 15 ट्रक से अधिक तेंदू और खैर की लकड़ी मिली, जिसे वन विभाग ने जब्त कर लिया है। शुरूआती जांच के अनुसार लकड़ी की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। दरअसल, वन विभाग को ट्रक और माजदा वाहन में बेशकीमती लकड़ी के परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। खबर मिलने के बाद रायगढ़ वन विभाग की उड़नदस्ता टीम जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना के भादा ग्राम पहुंची। जिसके बाद बंद पड़े राइस मिल के गोदाम को जांचा गया। जांच में वहां से करीब 15 ट्रक कीमती लकड़ी बरामद हुआ। बंद पड़े राइस मिल से जो लकड़ी बरामद की गई है वो तेंदू और खैर पेड़ की है। वन मंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे बताया, भादा गांव के बंद राइस मिल परिसर में अवैध आरा मिल संचालित होने

कैदी ने हंसिया से अपना गला रेतकर की खुदकुशी की कोशिश

बिलासपुर। बिलासपुर सेंट्रल जेल के किचन में काम कर रहे एक कैदी ने हंसिया से अपना गला रेतकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में जेल कर्मचारियों ने उसे तुरंत सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गला रेतने के बाद कैदी अभी बातचीत नहीं कर पा रहा है, इसलिए घटना के पीछे के कारणों की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर उसने यह कदम क्यों उठाया। जानकारी के अनुसार पेंड्रा निवासी विकास कश्यप हत्या के मामले में 2 साल से केंद्रीय जेल में सजा काट रहा है। कैदी विकास कश्यप ने पारिवारिक विवाद में अपनी दादी की हत्या कर दी थी। वर्ष 2024 में उसे उक्त मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उससे जेल के किचन में भोजन बनाने का काम फिलहाल लिया जा रहा है। मंगलवार की सुबह 7 बजे कैदी विकास अपने बैरक से जेल के किचन में भोजन बनाने के लिए पहुंचा। काम करने के दौरान उसने अचानक सब्जी काटने के हंसिया से गला रेत लिया। इस दौरान काम कर रहे अन्य कैदियों ने विकास को तड़पता देखकर उसे

संभाला और जेल के अधिकारियों को सूचना दी। कैदी के खुदकुशी करने की कोशिश करने की सूचना पर जेल में हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक, जेलर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद तत्काल जेल के एम्बुलेंस से गंभीर रूप से घायल कैदी को इलाज के लिए सिम्स ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। बहरहाल, कैदी के होश में आने पर घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी।

कारोबारी की कार बरामद, एसोशिएशन अध्यक्ष ने की सुरक्षा की मांग

बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर में बीती रात हुई करोड़ों की सनसनीखेज लूट ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। राजकिशोर नगर में महालक्ष्मी ज्वेलरी शॉप के संचालक संतोष तिवारी पर जानलेवा हमला कर लुटेरे करीब 3।35 करोड़ रुपये के जेवर और नकदी से भरी कार लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने उरतुम के पास से व्यापारी की कार बरामद कर ली है, हालांकि, लुटेरे कार में रखा करोड़ों का सोना और कैश लेकर भागने में सफल रहे। वारदात के बाद एक तरफ सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष ने व्यापारियों के लिए सुरक्षा की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए

स्थानीय विधायक से इस्तीफे की मांग कर दी है। पुलिस से जानकारी के अनुसार, सराफा कारोबारी संतोष तिवारी रोजाना की तरह दुकान बंद कर अपनी कार से घर लौट रहे थे। लुटेरों ने पहले से ही उनकी रैकी की थी और उनके रूट की पूरी जानकारी उनके पास थी। वसंत विहार चौक के पास हमलावरों ने व्यापारी पर हमला किया और उनकी कार समेत 2 किलो 200 ग्राम सोना, 3।50 लाख रुपये नकद और अन्य कीमती सामान लूट लिया। कुल मशरूका करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं इस वारदात में घायल कारोबारी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस को घटना के कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार लुटेरे दुकान बंद होने के समय से ही व्यापारी का पीछा करते नजर आ रहे हैं। वहीं, मौके पर पहुंचे स्निफर डॉग ने गंध सूंघने के बाद ओम पैलेस अटल आवास की तरफ दौड़ लगाई, जिससे आरोपियों के भागने की दिशा का पता चला है। पुलिस की कई टीमें अलग-अलग इलाकों में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।मामले में सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने आईजी रामगोपाल गर्ग से फोन पर चर्चा कर घटना की पूरी जानकारी साझा की। कमल सोनी ने कहा कि यह घटना बिलासपुर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट की वारदात है, जिसने व्यापारी समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की है।

वहीं पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विधायक से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि बिलासपुर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और जनता को सुरक्षा के नाम पर धोखा दिया गया है।

कमिश्नरेट रायपुर में डीसीपी कोर्ट की कार्यवाही शुरू

रायपुर। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम ऋद्धुद्धश्वह्नह्न. रायपुर। कमिश्नरेट रायपुर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद कार्यपालिक न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिनांक 16 फरवरी से एसीपी कोर्ट की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के पश्चात अब डीसीपी कोर्ट की कार्यवाही भी विधिवत शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में डीसीपी मध्य जोन उमेश गुप्ता ने अपने न्यायालयीन कार्य की औपचारिक शुरुआत की, जिसे कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से अहम विकास माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार,

कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद कार्यपालिक न्यायिक अधिकारों के तहत त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का उद्देश्य रखा गया है। डीसीपी कोर्ट की शुरुआत इसी दिशा में एक ठोस पहल है, जिससे आदतन अपराधियों और शांति भंग की आशंका वाले मामलों में समयबद्ध सुनवाई और कानूनी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रारंभिक कार्यवाही के तहत थाना मौदहापारा द्वारा प्रस्तुत एक इस्तगासा पर सुनवाई की गई। यह प्रकरण धारा 129 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो आदतन अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। सुनवाई के दौरान डीसीपी मध्य जोन द्वारा अनावेदक को विधिवत नोटिस जारी किया गया और मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की कार्यवाही से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में तत्कालिक और प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। डीसीपी कोर्ट के प्रारंभ होने से पुलिस प्रशासन को उन मामलों में त्वरित हस्तक्षेप का अवसर मिलेगा, जहां शांति भंग की आशंका, आदतन अपराध या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रश्न सामने आते हैं। अब ऐसे मामलों में लंबी प्रक्रिया के बजाय स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई और आवश्यक आदेश जारी किए जा सकेंगे। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, जो आम नागरिकों के लिए भी राहतकारी सिद्ध हो सकती है।पुलिस विभाग का मानना है कि कार्यपालिक न्यायिक शक्तियों का प्रभावी उपयोग अपराध नियंत्रण की रणनीति को मजबूत करेगा। विशेष रूप से आदतन अपराधियों के विरुद्ध निगरानी, बंधपत्र और अन्य कानूनी उपायों को लागू करने में डीसीपी कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इससे निवारक कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रमुख आधार है। कमिश्नरेट रायपुर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि डीसीपी कोर्ट की न्यायालयीन कार्यवाही नियमित और सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई कर कानूनी प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित किए जाएंगे। यह व्यवस्था शहर में कानून का राज स्थापित करने और अपराधों पर नियंत्रण की दिशा में एक सशक्त कदम के रूप में देखी जा रही है।

महिला पत्रकार क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता बनी शक्ति टीम, तेजस्वी रही उपविजेता

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई के अंतर्गत स्व0 कुलदीप निगम स्मृति इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट में महिला पत्रकारों का फाइनल मुकाबला आज सुभाष स्टेडियम में उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। फाइनल मैच में शक्ति टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि तेजस्वी टीम उपविजेता रही।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विजेता शक्ति टीम और उपविजेता तेजस्वी टीम को बधाई देते हुए दोनों टीमों के लिए 21-21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की।महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की आधारशिला हैं।

पत्रकारों की व्यस्त दिनचर्या के बीच महिला पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी प्रेरणादायक है। ऐसे आयोजन कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी समन्वय और टीम भावना को सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग रायपुर की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा, पार्षद श्रीमती अंजुम ढेबर सहित वरिष्ठ पत्रकार मंजूषा शर्मा, श्रीमती शशि परगनिया, आफताब बेगम, शताब्दी पाण्डे एवं श्रीमती ज्योति सिंह ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति रही।

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर स्थित पहुना अतिथि गृह में उनसे सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न जनकल्याणकारी विषयों पर सकारात्मक एवं विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, पोषण स्तर में सुधार, सुरक्षा तंत्र की मजबूती तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से योजनाओं को और अधिक परिणाममूलक बनाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रदेश में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है तथा जमीनी स्तर पर योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा भी उपस्थित रहीं। उन्होंने बाल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों एवं पहलों की जानकारी साझा की।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज से लिया आशीर्वाद

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज

कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बुधवार को रायपुर में परम पूज्य निरंजनी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के दिव्य दर्शन कर उनका स्नेहिल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि संत महापुरुषों का सन्निध्य समाज को सेवा, संस्कार और मानव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। उनके विचार समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तथा जनसेवा के कार्यों को अधिक समर्पण भाव से करने की शक्ति प्रदान करते हैं। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा हमारी सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण पहचान है। इस परंपरा को संरक्षित एवं संवर्धित करना हम सभी का दायित्व है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा तथा आईएनएच-हरिभूमि के संपादक श्री हिमांशु द्विवेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से बुधवार को महानदी भवन में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने 21 व 22 फरवरी 2026 को बलौदाबाजार - भाटापारा जिले के ग्राम चाँपा (सैंहा)में आयोजित हो रहे 80 वॉ छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज महा-अधिवेशन के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा,केन्द्रीय महामंत्री यशवंत सिंह वर्मा, कोषाध्यक्ष जागेश्वर बघेल, राज प्रधान बलौदाबाजार श्रीमती सुनीता वर्मा,चन्दखुरी चिन्ता राम वर्मा, रायपुर जगेश्वर प्रसाद वर्मा अर्जुन राज हरी राम वर्मा ,हरिश्चंद्र वर्मा, रघुनंदन वर्मा सहित समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

राजस्व मंत्री ने नागरिकों के हितों से जुड़ी भू-अभिलेख पुस्तकों का किया विमोचन

रायपुर। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने बुधवार को निवास कार्यालय में भू-अभिलेख नियमावली भाग 1 से 4 पुस्तक का विमोचन किया।श्रीी उमेश पटेल और श्री श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखित इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के सर्कुलर और आदेशों का संकलन है। अभी तक मार्केट में जो पुस्तक थी, उसके लेखक और प्रकाशक मध्य प्रदेश के हैं। इसके कारण मध्यप्रदेश के सर्कुलर और आदेश उस पुस्तक में मिलते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के नहीं।अब इस पुस्तक में, वर्ष 2000 के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी सर्कुलर जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं है, उन्हें नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ द्वारा जारी अद्यतन सर्कुलर को अध्याय-वार दिया गया है। परिशिष्ट के रूप में सर्वे, राजस्व वन भूमि के अभिलेख, गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे आदि महत्वपूर्ण विषयों पर जारी लेटेस्ट सर्कुलर शामिल किए गए हैं। विषय से संबंधित प्रश्न, इकाई परिवर्तन, शब्दार्थ आदि का भी समावेश किया गया है।

शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का फायदा हितग्राहियों को समय पर मिले: मुख्य सचिव

■ राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों से कहा है कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का फायदा हितग्राहियों को समय पर मिले यह सुनिश्चित हो। इसके लिए पहले से ही हितग्राही से संबंधित जानकारी दुरस्त कर लिया जाये। मुख्य सचिव आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित जनगणना वर्ष 2027 के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में सभी जिलों में पेयजलापूर्ति, गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से पहले से ही लोगों को सावधान रहने एवं बचाव करने जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्ययोजना बनाने और तैयारियां पहले से ही कर लें। कलेक्टर्स को इस वर्ष खरीफ मौसम की धान खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने, राशन दुकानों में खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता, इस साल तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा, जनसमस्याओं के समाधान एवं निवारण, पीएम आवास सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को जनगणना वर्ष 2027 संबंधी कार्यों को सतर्कता एवं संवेदनशीलता से करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गये।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी राशनकार्ड धारकों को पात्रता के अनुसार समय पर खाद्यान्न सामग्री मिले इसके लिए लगातार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की मानीटरिंग करें। मुख्य सचिव ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान संग्रहण केन्द्रों के भौतिक सत्यापन कर धान परिवहन एवं मिलिंग कार्य करने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मिलर्स के लंबित भुगतान करने जरूरी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कृषि विभाग एवं मार्कफेड के अधिकारियों को आगामी खरीफ मौसम में खाद एवं बीज के पर्याप्त भंडारण करने कहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह ने कलेक्टरों को लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं निवारण के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करने कहा है। उन्होंने विभिन्न शासकीय लंबित भुगतान करने शिविर शिविर लगाकर कार्यवाही करने कहा है।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने कलेक्टर्स को भारत की जनगणना 2027 से संबंधित कार्य के संबंध दिशा निर्देशों के संबंध विस्तार से बताया। राज्य स्तरीय संभागायुक्त कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिव, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स, नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का किया शुभारंभ

■ गुरु घासीदास के अनुयायियों का दल पावन गिरौदपुरी धाम के लिए हुआ रवाना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बुधवार को राजधानी रायपुर के मोवा स्थित सतनाम भवन परिसर से विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने धार्मिक विधि-विधान के साथ पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर पावन गिरौदपुरी धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पवित्र जैतखाम की पूजा-अर्चना कर गुरु घासीदास बाबा का पुण्य स्मरण किया तथा प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और सामाजिक बंधुओं से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि गुरु घासीदास बाबा का मनखे-मनखे एक समान का संदेश संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पदयात्रा समाज में सद्भावना, समरसता और भाईचारे को और सुदृढ़ करेगी। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक हितों को गति देने हेतु विशेष प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। पदयात्रा के उपरांत विशाल मेले के आयोजन की जानकारी भी उन्होंने दी।

कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि यह पदयात्रा सामाजिक समरसता, मानव कल्याण और एकता के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। उन्होंने सभी से सामाजिक भेदभाव और द्वेष से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान

किया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह यात्रा गुरु घासीदास बाबा के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाएगी।

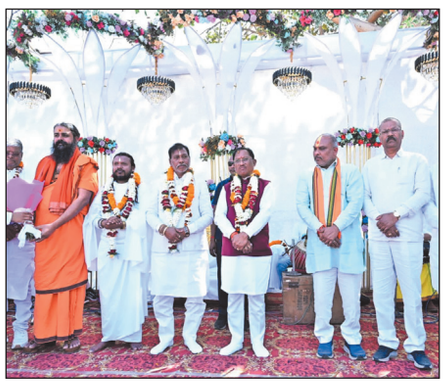

कार्यक्रम में धर्मगुरु गुरु श्री बालदास साहेब, विधायक श्री ललित चंद्राकर, विधायक श्री मोतीलाल साहू, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, संत समाज के प्रतिनिधि एवं सर्व समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि रायपुर से गिरौदपुरी धाम तक प्रस्तावित विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का आयोजन 18 से 22 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। पदयात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा और सद्भाव का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। इस दौरान गिरौदपुरी धाम मेले में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए।

होली के दिन शराब दुकान खुली रखने पर कांग्रेस ने बोला हमला

मंत्री गुरू खुशवंत और विधायक पुरंदर मिश्रा ने दिया जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक बार फिर सियासत तेज है। होली के दिन शराब की दुकानें खुलने के फैसले पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बोला हमला है। इस पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर ही सवाल उठाया है।

कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा होली महत्वपूर्ण त्योहार है। सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होली के समय होती है। लेकिन इस बार होली के दिन भी शराब दुकान खुली रहेगी। कैसा माहौल रहेगा समझा जा सकता है, लेकिन भाजपा को शराब से पैसा कमाना है। भाजपा सरकार प्रदेश को नशे में झोंकने का काम कर रही है।

वहीं प्रदेश की नई आबकारी नीति में 7 दिन की जगह 3 दिन ड्राई डे रखे जाने का मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने बचाव करते हुए कहा कि यह सभी निर्णय समय के अनुसार लिए जाते है। हम सब का एक ही भाव है कि सभी नशे से दूर रहें। गुरु घासीदास बाबा ने कहा है कि खानी, बानी और सयानी। जैसा खाएंगे वैसा रहेगा मन, जैसा पियेंगे पानी, वैसे रहेगी वाणी। नशे के खिलाफ सरकार जनजागरुकता अभियान चला रही है। पदयात्रा में भी उसी संदेश को प्रचारित किया जाएगा कि नशे से सभी दूर रहें।

वहीं त्योहारों पर शराब दुकानों के खुले रखने पर कांग्रेस के तंज पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का यह दुर्भाग्य है कि रात-दिन कांग्रेसी नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। आंदोलन, प्रदर्शन से जनता को डरा रहे हैं। जनता ने बीजेपी को पंच से पार्लियामेंट तक आशीर्वाद दिया है। साय सरकार जनता के हित में काम कर रही है। 3200 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले हमको बुद्धि ना दें। हमको श्रीराम ने बुद्धि दिया, भगवान ने बुद्धि दिया है।

ग्रामीण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार एसडीएम करुण डहरिया निलंबित

रायपुर। साय सरकार ने आदिवासी किसान की पिटाई से मौत के मामले में सख्ती दिखाते हुए आरोपी एसडीएम करुण डहरिया को निलंबित कर दिया है। मामले में पहले ही एसडीएम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। निलंबन की अवधि में करुण डहरिया मुख्यालय सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है।

जानकारी के अनुसार, 15-16 फरवरी की दरमियानी रात को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी ब्लॉक में हंसपुर गांव में बॉक्साइट के अवैध खनन की जांच करने के लिए कुसमी एसडीएम करुण डहरिया गए हुए थे। आरोप है कि वह प्राइवेट गाड़ी में प्राइवेट लोगों को लेकर पहुंचे हुए थे। सरना के पास तीन ग्रामीणों को एसडीएम और उनके साथ गए प्राइवेट लोगों ने रोका एवं पूछा कि कहां से आ रहे हो। इसके बाद अवैध उत्खनन का आरोप लगा रॉड, डंडे और लात-घूंसों से पिटाई कर दी। ग्रामीणों को बेहोश होने तक के पीटा गया। मारपीट में घायल ग्रामीणों को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 62 वर्षीय ग्रामीण रामनरेश राम की मौत हो गई। वहीं 60 वर्षीय अजीत उरांव और 20 वर्षीय आकाश अगरिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में घायल ग्रामीण आकाश अगरिया एवं अजीत उरांव ने बताया कि वे गेहूं के खेत में पानी की सिंचाई करने गए हुए थे। लौटने के दौरान बिना किसी पूछताछ या जांच अवैध खनन का आरोप लगा उनकी पिटाई की गई।

घायल ग्रामीणों के बयान के आधार पर कुसमी एसडीएम करुण डहरिया और उनके साथ गए उनके बाहरी साथी विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजिल कुमार यादव व सुदीप यादव के खिलाफ राजपुर थाने में धारा 103, 115 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

एसडीएम की पिटाई से आदिवासी किसान की मौत पर भूपेश बघेल की तल्ख टिप्पणी

बलरामपुर जिले के कुसमी में एसडीएम द्वारा की गई मारपीट से आदिवासी किसान की मौत के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना पर तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे प्रदेश में गिरती कानून-व्यवस्था के उदाहरण के तौर पर पेश किया है।

पंजाब दौरे से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था की स्थिति बेहद ख़राब है। हद तो यह है कि प्रशासन के लोग ही हत्या करने लगे हैं। विष्णु देव सरकार और विजय शर्मा के विभाग के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। वृद्ध आदिवासी को पीट-पीट कर मार डाला।

अब महतारी सदन का निर्माण करेंगी ग्राम पंचायतें

■ पंचायतों को सशक्त करने के लिए उपमुख्यमंत्री शर्मा की पहल पर लिया गया निर्णय

रायपुर। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायतों को अधिक अधिकार देने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर अब महतारी सदनों का निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। लंबे समय जनप्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए लिए गए इस निर्णय से जहां एक ओर पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए सशक्त मंच उपलब्ध होगा। महतारी सदन महिलाओं के लिए बैठक, प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह की गतिविधियों एवं आजीविका संवर्धन का केंद्र बनेंगे।

ग्राम पंचायतों को कार्य एजेंसी बनाये जाने पर कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके लिए विभाग द्वारा मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। जिसके अनुसार महतारी सदन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जाएगी तथा तकनीकी मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृति के लिए निश्चित प्रक्रिया भी तय की गयी है। कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रतिवदेन जिला पंचायत के माध्यम से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक संचालक पंचायत, संचालनालय छत्तीसगढ़ को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् एक माह के भीतर कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा तथा 6 से 8 माह के भीतर कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी कार्य पंचायतों की होगी।

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बीजापुर
Tel. No. 07853-220082, E-Mail ID eebil-phe-cg@nic.in

निविदा क्र. / 29 /त.शा/का.अ./ लो.स्वा.यां. / खण्ड 2026 — बीजापुर दिनांक 13/2/2026

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ के राज्यपाल की ओर से मुहरबंद निविदाएँ प्रपत्र " अ" प्रतिशत दर पर बीजापुर जिला अन्तर्गत विकासखण्ड़ बीजापुर/भैरमगढ़ / भोपालपटनम में नियद नेल्लानार योजना के तहत चयनित ग्रामों में स्वीकृत नलजल योजनाओं के लिए नलकूप खनन कार्य हेतु जिला खनिज न्यास मद (DMF) वित्तीय वर्ष 2025 -26 में प्राप्त आबंटन की प्रत्याशा में कार्यपालन अभियंता, लो. स्वा.यॉ. खण्ड बीजापुर को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह कार्य जिला खनिज न्यास मद अन्तर्गत स्वीकृत राशि से स्वीकृत नलजल योजनाओं में 150 मिमी. व्यास के 90 मीटर नलकूप खनन् कार्य के लिए डी या उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां. खण्ड बीजापुर में आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्य में प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग रायपुर छ.ग. के यु.एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020 में Amedment date 18.04.2023 (Amedment No. 09/2023-24) से प्रभावशील एवं निविदा जारी होने की तिथि तक समस्त संशोधन सहित लागू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 05.03.2026 को शाम 5.30 बजे तक तथा निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 06.03.2026 शाम 5.30 तक है। निविदा प्रपत्र का मूल्य- 750/-

समूह क्र.	विकास खण्ड	नलकूप की संख्या	अनु. लागत (लाख में)	धरोहर राशि (FDR)
1	2	3	4	5
1	बीजापुर / भैरमगढ / भोपालपटनम	20	14.038	10600/

टीप- निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण नियम व शर्ते आदि की जानकारी कार्यालयीन अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।

जी-252606747/4

कार्यपालन अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बीजापुर (छ.ग.)

कार्नी ने एक बड़ा एंटी-ट्रम्प ट्रेड अलायंस बनाया

ग्राहम लैंकट्री

दुनिया के दो सबसे बड़े ट्रेडिंग ग्रुप डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ को कम करने के लिए सावधानी से करीबी रिश्ते बनाने पर नजर रख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और 12 देशों का इंडो-पैसिफिक ब्लॉक सबसे बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक अलायंस में से एक बनाने के प्रस्तावों पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। कनाडा इस बातचीत का नेतृत्व कर रहा है, जब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीने मिडिल पावर्स से ट्रेड वॉर के दबाव को कम करने की अपील की थी। कुछ ही दिनों पहले ट्रम्प ने डेनमार्क के यूरोपियन सहयोगियों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, अगर उन्होंने ग्रीनलैंड नहीं छोड़ा। ओटावा ''ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप और यूरोपियन यूनियन के बीच एक पुल बनाने की कोशिशों को सपोर्ट कर रहा है, जिससे 1.5 बिलियन लोगों का एक नया ट्रेडिंग ब्लॉक बनेगा।'' कार्नी ने दावोस में दुनिया के नेताओं और ग्लोबल बिजनैस इलीट से कहा। मिडिल पावर्स कार्रवाई कर रही हैं। ई.यू. और सी.पी.टी.पी.पी. इस साल कनाडा, सिंगापुर, मैक्सिको, जापान, वियतनाम, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे सदस्यों की सप्लाई चेन को यूरोप के साथ जोडऩे के लिए एक समझौता करने के लिए बातचीत शुरू कर रहे हैं। इससे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के करीब 40 देश एक-दूसरे के करीब आएंगे, जिसका मकसद तथाकथित रूल्स ऑफ ओरिजिन पर एक डील करना है। ये नियम किसी प्रोडक्ट की इकोनॉमिक नैशनैलिटी तय करते हैं। एक डील से दोनों ब्लॉक के मैन्युफैक्चरर कम टैरिफ प्रोसैस में सामान और उनके पार्ट्स का आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, जिसे क्यूम्युलेशन कहते हैं। इस महीने की शुरुआत में, कार्नी ने यूरोपियन यूनियन में अपने निजी प्रतिनिधि जॉन हैनाफोर्ड को संभावित डील पर रीजनल लीडर्स की राय जानने के लिए सिंगापुर भेजा था। कनाडा सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ''काम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। हमने दुनिया भर के दूसरे पार्टनर्स के साथ इस पर बहुत फायदेमंद बातचीत की है।'' ई.यू. और इंडो-पैसिफिक क्लब, जिसे कॉम्प्रिहैंसिव एंड प्रोग्रैसिव एग्रीमैंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सी.पी.टी.पी.पी.) के नाम से जाना जाता है, ने पिछले नवम्बर में ट्रम्प के 'लिबरेशन डे' टैरिफ के बाद फ्री ट्रेड के बिखराव को रोकने के लिए अपनी आर्थिक ताकतों को मिलाने का फैसला किया था। एक जापानी ट्रेड अधिकारी ने कहा, ''हम ई.यू. और सी.पी.टी.पी.पी. पार्टियों के बीच ट्रेड बढ़ाने में बहुत वैल्यू देखते हैं, जो सप्लाई चेन की मजबूती को बढ़ाने में भी मदद करेगा।'' एक दूसरे सी.पी.टी.पी.पी. देश के एक ट्रेड डिप्लोमैट ने कहा, ''अगर ई.यू. बातचीत के लिए तैयार है, तो बेशक यह चीजों को वाकई बहुत दिलचस्प बना देगा।'' हालांकि यह डील ''वाकई ई.यू.-सी.पी.टी.पी.पी. सहयोग के बड़े दायरे का हिस्सा है।'' हालांकि, पूरे यूरोप में बिजनैस ग्रुप रूल्स-ऑफ ओरिजिन डील के सपोर्ट में जोर-शोर से आगे बढ़ रहे हैं और ब्रसल्स और लंदन को आगे बढऩे के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डी.आई.एच.के.) और ब्रिटिश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इस समझौते का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। डी.आई.एच.के. में ट्रेड पॉलिसी, ई.यू. कस्टम्स और ट्रांसअटलांटिक रिलेशंस के डायरैक्टर क्लेमेंस कोबर ने कहा कि 'हमें उम्मीद है कि अगर यह सफल होता है, अगर आप अलग-अलग एरिया में ठोस फायदे देख सकते हैं, तो यह दूसरे देशों को भी इसमें शामिल होने और पॉजिटिव तरीके से टीम बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।' 'तो जितने ज्यादा होंगे, उतना अच्छा होगा।'

अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट

अभिनय आकाश

भारत अब ग्लोबल एआई हब बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन चल रहा है। यह समिट किसी विकासशील देश में होने वाला पहला बड़ा एआई शिखर सम्मेलन माना जा रहा है। समिट की थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी एआई का विकास सबके लिए और सबके हित में। यह शिखर सम्मेलन तीन सूत्रों पर आधारित है। लोक, पृथ्वी और प्रगति। फोकस रहेगा कि एएआई का इस्तेमाल आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए कैसे किया जाए। इस समिट में 500 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स अपने इनोवेशन का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सात देशों के राष्ट्रपति, दो उपराष्ट्रपति, नौ प्रधानमंत्री और कई बड़े कंपनियों के सीईओ इसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार पहले ही मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे चुकी है। इसके लिए 5 साल का करीब 10,372 करोड़ का बजट तय किया गया है। एआई समिट का एजेंडा सिर्फ टेक्नोलॉजी पर चर्चा करना नहीं है बल्कि एक्शन से बैक तक एआई के सफर को आगे बढ़ाना है। इस बार फोकस साफ है एआई को सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल की बहस ना बनाकर उसे जमीन पर बदलाव लाने वाला टूल बनाना।

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन की पहल है। यह 5 दिन का कार्यक्रम है, जिसमे पॉलिसी, रिसर्च, इंडस्ट्री और आम भागीदारी, सबको जोड़ा गया है। सरकार ने इस समिट की थीम रखी है- सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय यानी एआई का इस्तेमाल सबके भले और खुशहाली के लिए हो।

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में टेक लीडर्स भविष्य का प्लान बताएंगे। यहां एक बड़ा एक्स्पो भी लगेगा। एक्स्पो में 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट दिखाए जाएंगे। यहां लोग जान सकेंगे कि अभी एआई में क्या नया हो रहा है और भविष्य में क्या बदलाव आने वाले है। एक्सपर्ट बताएंगे कि अब तक क्या रिसर्च हुई है और आगे किन विषयों पर काम चल रहा है। एआई से जुड़े कौन-कौन से चैलेंज है।

यह सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि 21वीं सदी में डिजिटल ताकत का एक बहुत बड़ा संकेत देता हुआ समिट है। समिट का उद्देश्य है कि एआई आम लोगों की जिंदगी में सीधे असर डाले। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार। पूरा एजेंडा तीन सूत्रों में बांटा गया है और इसे सात चक्रों के विस्तृत रोड मैप के जरिए लागू करने की योजना है। इसमें समावेशी और जिम्मेदार एआई पर खास जोर रहेगा ताकि तकनीक का फायदा हर वर्ग तक पहुंचे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में एआई की भूमिका पर भी चर्चा होगी। आर्थिक विकास और उत्पादकता बढ़ाने में एआई कैसे मददगार बने यह भी एजेंडे का अहम हिस्सा है। और जैसा कि हमने बताया कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में इस बार सिर्फ टेक्नोलॉजी की चर्चा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एआई और राजनीतिक नेता एक मंच पर नजर आएंगे।

सबसे पहले 1-2 नवबर 2023 को ब्रिटेन समिट में एआई से जुड़े खतरों और सुरक्षा पर चर्चा हुई थी। इसके बाद 21-22 मई 2024 को साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में एआई को सुरक्षित और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। फिर 10-11 फरवरी 2025 को फ्रांस के पैरिस में एआई ऐक्शन समिट में सार्वजनिक हित और टिकाऊ विकास से जोड़ने पर चर्चा हुई थी।

पीपुल: एआई हर इंसान की मदद के लिए हो, चाहे वो गांव का किसान हो या शहर का स्टूडेंट। इस सूत्र का मकसद है कि आम से खास तक एआई की पहुंच हो, ताकि कोई पीछे न छूट जाए। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते है, ये सूत्र एआई को लोकल बनाने पर फोकस करता है। मतलब ऐसा एआई सिस्टम जो आम लोगों की मदद करे, रोजगार बढ़ाए और सिक्योरिटी को मजबूत करे।

प्लानेट: यह सूत्र कहता है कि एआई इनोवेशन को पर्यावरण की देखभाल और सस्टेनेबिलिटी से जोड़ा जाए। जैसे, खेती में एआई मौसम बताता है, ड्रोन से फसल की निगरानी करता है ताकि पानी और खाद बर्बादी न हो। स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक कंट्रोल करता है, कचरा मैनेज करता है। डेटा सेंटरों से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने के तरीके सुझाता है। मतलब, ऐसा एआई सिस्टम हो, जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके।

प्रोग्रेस: यह सूत्र एआई के फायदों को सबके साथ बांटने पर जोर देता है, ताकि वैश्विक विकास हो। यह कहता है कि एआई से समृद्धि सब तक पहुंचे। गवर्नमेंट सर्विसेज, सर्विस डिलिवरी, मोबिलिटी यानी आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाए। यह सूत्र एआई को आर्थिक ग्रोथ का इंजन बनाता है, जहां गांव-शहर सबका विकास हो। दुनिया के देश मिलकर एआई शेयर करेंगे, ताकि गरीब देश भी अमीर बन सके।

ब्रिटेन की 2023 की समिट में गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, जवाबदेही और मानव निगरानी जैसे मुद्दों को उठाया। सबसे पहले 1-2 नवबर 2023 को ब्रिटेन समिट में एआई से जुड़े खतरों और सुरक्षा पर चर्चा हुई थी। इसके बाद 21-22 मई 2024 को साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में एआई को सुरक्षित और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया। फिर 10-11 फरवरी 2025 को फ्रांस के पैरिस में एआई ऐक्शन समिट में सार्वजनिक हित और टिकाऊ विकास से जोड़ने पर चर्चा हुई थी। सियोल मे एआई में जोखिम को समझने और जाचने के लिए वैज्ञानिक सहयोग जरूरी है। पैरिस 2025 की समिट में कहा गया कि एआई का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए होना चाहिए।

लोगों को एआई के वास्तविक उपयोग के वारे में पता चलेगा, जैसे शिक्षा, हेल्थ, खेती और सरकारी सेवाओं में कैसे एआई मदद कर सकता है। एआई सबके लिए उपलब्ध और उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक। कई देश और संस्थान इसका डेमो दिखाएंगे। नई नौकरियों के बनाने और कौशल सीखने में एआई ने कैसे मदद की, कंपनियां और देश इसका प्रैक्टिकल अनुभव भी दिखाएंगे। किसानों, छात्रों, शिक्षकों और छोटे कारोवारों को ऐसे एआई टूल्स के बारे में जानकारी मिल सकती है जिससे उनका काम आसान बन सकेगा।

अमेरिका या चीन की तुलना में भारत का एआई सफर अभी बस शुरू ही हुआ है। सरकार ने मार्च 2024 में %इंडिया एआई मिशन% की शुरुआत की थी। इस मिशन में सेमीकंडक्टर, एआई और मशीन लर्निंग वगैरह के लिए कई पहल की गई हैं। सरकार विदेशी क्लाउड कंपनियों को भी देश में ही डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए लुभा रही है। इम्पैक्ट समिट से इन सारे प्रयासों को बल मिलेगा।

एआई की सबसे बड़ी जरूरत है डेटा और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन, केवल लर्निंग का मैदान बनने से काम नहीं चलेगा। भारत को अपना डेटा सेंटर और अपना एआई मॉडल चाहिए। इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे तेजी से डिवेलप करने होंगे। यह तकनीक की दौड़ ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। देश को अगर यूजर से आगे बढ़कर डिवेलपर बनना है, तो रफ्तार बढ़ानी होगी। इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट वह मौका है, जहां भारत अपनी क्षमता और महत्वाकांक्षा -दोनों दिखा सकता है। किसी भी तकनीक का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है, जब वह सभी के लिए सुलभ हो। भारत का मानना रहा है कि टेक्नॉलजी तक हर किसी की पहुंच होनी चाहिए, ताकि सभी को बराबर मौके मिलें। समिट को जिन 7 प्राथमिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उनमें एक है डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज वर्किंग ग्रुप। यह बताता है कि भारत एआई को समावेशी विकास के टूल के रूप में देखता है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इस तरह कहते हुए विष्णु भगवान् वहीं अन्तर्धान हो गए।॥ 17 ॥ [अनन्तर मोहिनी रूप में प्रकट होने के बाद शिवजी दर्शनीय रूप लावण्य से युक्त एवं सुन्दर कटाक्ष वाली उस स्त्री को देख कर मुग्ध हो गए॥24।। उस समय मोहिनी के पीछे भागते हुये, अमोधवीर्य भगवान् शंकर का वीर्य गिर पड़ा।। 32।। [जहाँ जहां वीर्य गिरा] वे सब क्षेत्र सोने और चांदी की खानें बन गई।॥ 33 ॥

विज्ञ पाठक उपर्युक्त वैदिक और पौराणिक दोनों स्वरूपों की तुलना करने के बाद अवश्य इसी परिणाम पर पहुँचेंगे कि वेदों में तो पुराणों से भी अधिक खुले शब्दों में वीर्य का गिरना, और उससे सुवर्णादि धातुओं का बन्ना लिखा है। इसमें यदि कुछ भेद है तो यह है कि पुराणों में जहाँ मोहिनी रूप के पीछे भागने मात्र से वीर्य का गिर जाना लिखा है प्रौर सभ्यता की रक्षा के लिये दूर दूर की दौड़ धूप तक की चेष्टा का ही जल्लेख किया है, वहाँ वेदों में तो स्पष्टतया रम्यायाँ तन्वां देवा अरमन्त, मिथुनान्याभि: स्याम् आदि शब्दों द्वारा समस्त देवताओं का मोहिनी से रमण करना-तथा मिथुनीभाव को प्राप्त होना तक भी खुले शब्दों में लिख डाला है। इस तरह शङ्कावादी जो ग्राक्षेप पुराणों पर करना चाहता था उससे भी अधिक वह दोष वेदों पर आ पड़ता है। सो जो समाधान प्रतिवादी के मत में वैदिकस्वरूप का होगा वही हमारे पौराणिक-स्वरूप का भी समझ लेना चाहिये। क्योंकि -ययोरेव समो दोष: परिहारस्तयो: सम: यही न्याय है।

वास्तविक भाव

उपर्युक्त आख्यान अत्यन्त गूढ़ एवं लोकोत्तर विज्ञान से परिपूर्ण है। आजकल भौतिकविज्ञान (साइन्स) का युग माना जाता है, पाश्चात्य शिक्षा दीक्षासम्पन्न, समालोचक दर्तमान साइन्स का बड़ा भारी घमण्ड रखते हैं। **क्रमश:...**

गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी मानते थे अपना राजनीतिक गुरु

धीरज पाल

आज ही के दिन यानी 19 फरवरी को महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया था। गोखले मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये वही नेता हैं जिसने सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बताए जा रहे विधेयक के विरोध में लेजिस्टलेटिव बार काउंसिल से वॉक आउट कर दिया था। इनकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण की वजह से महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों ही इन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। गांधी और जिन्ना गोपालकृष्ण गोखले को क्यों अपना राजनैतिक गुरु मानते थे, इसे जानने के लिए सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ बाते जान लेनी चाहिए।

गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ई में जिला रत्नागिरी, तालुका गुहागर के कोथलुक नामक गांव में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि गोखले अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और ब्रिटिश राज में कोई छोटी-मोटी नौकरी कर सकें।

गोखले सन 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। वे हमेशा जनता की परेशानियों के लिए कार्यरत रहे। कुछ समय के बाद बाल गंगाधर तिलक के साथ गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। हालांकि दोनों में काफी मतभेद थे जिसकी वजह से सन् 1905 में गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और कांग्रेस को भागों में बट गई। जहां तिलक ब्रिटिश सरकार को क्रांति कर आजादी लेना चाहते थे तो वहीं गोखले शांतिपूर्ण वार्ता और समन्वयवादी नेता थे।

कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गोखले ने सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसके पीछे गोखले का मकसद था कि भारतीयों को जागरुक और शिक्षित करना। इस सोसाइटी ने कई स्कूल, कॉलेज की स्थापना की गई।

सन् 1912 में गांधीजी के आमंत्रण पर गोखले ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। यात्रा के बाद गांधी और गोखले ने एक साथ कई महीने साथ बिताएं। उस दौरान गांधी जी नए-नए बैरिस्टर बने थे और साउथ अफ्रीका में अपने आंदोलन के बाद भारत लौटे थे। इसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में किया था। उन्होंने भारत के बारे में और भारतीय विचारों को करीब से जानने व समझने के लिए गोखले का साथ चुना और उनके परामर्श के अनुसार कार्य किए।

ऐसा नहीं था कि गोखले सिर्फ गांधी को प्रिय थे या अपना उन्हें राजनैतिक गुरु मानते थे। उस समय के एक और नेता मोहम्मद अली जिन्ना गोखले से इतने प्रभावित थे। जिन्ना ने एक तकरीर के दौरान कहा था कि अगर मैं मुसलमान गोखले बन सका तो मेरा जीवन सफल होगा। कुछ इस तरह थे गोपालकृष्ण गोखले।

गोखले अपना सारा जीवन भारत को को आजाद और राजनैतिक सक्रियता में दे दिया। उनकी मृत्यु सन 19 फरवरी सन् 1915 को हुई। उस वक्त उनकी उम्र महज 49 वर्ष की थी।

राहुल ने ट्रेड डील पर शाह की चुनौती की कबूल!

अभिनय आकाश

भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का जिसको लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही है। आरोप है कि अमेरिका के सामने मोदी सरकार झुक गई। सरकार का कहना है कि राहुल गांधी इस बारे में भ्रम फैला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि वो गुमराह करें कि यूरोपियन यूनियन इंग्लैंड इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। किसी भी मंच तय कर लो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं। कांग्रेस इसी बहाने फिर से देश भर के किसान संगठनों को एकजुट करने में जुटी है। राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा के कई किसान नेताओं से मुलाकात की है। मुद्दा अमेरिका के दबाव में रूस से सस्ता तेल ना खरीदने से लेकर किसानों के हितों की अनदेखी है। खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। अमेरिका ने बांग्लादेश से भी व्यापार समझौता किया है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि अमेरिका से हुए समझौते के बाद भारत का क्या नुकसान है। तमाम आरोपों के बीच भारत अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील मार्च तक होने के आसार हैं। भारतीय टीम अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बार फिर से बयान दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बटरल ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर बातचीत तय कार्यक्रम के हिसाब से आगे बढ़ रही है। खासतौर से अगले हफ्ते चीफ नेगोशिएटर के अध्यक्षता में एक टीम अमेरिका जा रही है और इस वक्त भी काफी कामकाज चल रहा है। खासतौर से जो डील होने वाली है उसको लेकर

एक तरह से जो लीगल वेटिंग का काम चल रहा है लैंग्वेज पर कंट्रो के डील के उसके लीगल लैंग्वेज पर काम चल रहा है। निर्देश काम कर रहे हैं और तय कार्यक्रम के हिसाब से अह चीज़ आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इस डील को जल्द से जल्द अमली जमा पहनाया जाए। लेकिन अभी इसके जो टाइम लाइन है उसको लेकर अभी कोई कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर की जा रही है कि जो मिनी फ्रेमवर्क है यानी कि डील का जो पहला हिस्सा है वो अपने तय कार्यक्रम मार्च के पहले करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मार्च तक होना संभव है। रही बात इजराइल और भारत के साथ डील वो भी कोशिश चल रही है और यूके के साथ जो डील लागू होने की बात है वो अप्रैल तक लागू हो जाएगी। जहां तक यूएस के साथ जो कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। खासतौर से एक बार सरकार ने फिर कहा है कि जीएम क्रॉप को बिल्कुल भारत में कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। बायो सिक्योरिटी को लेकर जो भी कंसर्न्स है उस कंसर्न्स को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कोई भी जीएम क्रॉप भारत में अंदर नहीं आएगी। तो अभी तक जो डील है उसको लेकर ये स्टेटस है और आने वाले दिनों में डील को डील को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने घोषणा की कि भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की कानूनी शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करेगा। इस समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने और लागू होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव दर्पण जैन, जो वार्ता के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार हैं, 23 फरवरी को वाशिंगटन के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वार्ता की प्रगति के बारे में अग्रवाल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वर्चुअल बैठकें पहले से ही चल रही हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ वर्चुअल बैठकें चल रही हैं और अगले सप्ताह मुख्य वार्ताकार कानूनी समझौते के लिए कानूनी ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस पर काम अगले सप्ताह वाशिंगटन में जारी रहेगा।

उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका द्वारा हाल ही में जारी संयुक्त बयान में अंतरिम समझौते की व्यापक रूपरेखा दी गई है, जिसे अब कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते में बदलना होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि संयुक्त बयान में समझौते की रूपरेखा निर्धारित की गई है। अब इस रूपरेखा को कानूनी समझौते में बदलना होगा, जिस पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे। इस महीने की शुरुआत में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की थी कि उन्होंने व्यापार को अधिक पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के उद्देश्य से एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है।

इस समझौते के तहत, भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह कटौती वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी।

अंतरिम समझौते के सफल समापन के बाद, सामान्य दवाइयों, रत्नों और हीरों तथा विमान के पुर्जों जैसे उत्पादों पर भी टैरिफ हटाए जाने की संभावना है। भारत की ओर से, नई दिल्ली ने कई अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कृषि एवं खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त करने या कम करने पर सहमति जताई है, जिनमें सूखे अनाज, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट शामिल हैं।हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि गेहूं, चावल, मक्का, दूध, मुर्गी पालन और कुछ सब्जियों जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों को संरक्षण प्राप्त रहेगा। इस रूपरेखा में दोनों देशों की व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने महीनों के व्यापारिक तनाव के बाद फरवरी 2025 में शुरू किया था।

वाणिज्य मंत्रालय ने अद्यतन व्यापार आंकड़े भी जारी किए, जिनमें निर्यात में समग्र वृद्धि को दर्शाया गया है। जनवरी 2026 में भारत का कुल माल और सेवाओं का निर्यात 80.45 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो जनवरी 2025 में 71.09 अरब अमेरिकी डॉलर था। इसी अवधि में आयात बढ़कर 90.83 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 76.48 अरब अमेरिकी डॉलर था। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 5.39 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में बढ़कर 10.38 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। अग्रवाल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जनवरी तक का संचयी निर्यात 720.76 अरब अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 679 अरब अमेरिकी डॉलर था। उन्होंने कहा कि यह अनुमानित 6.15% की वृद्धि है और लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गई है।

आज का इतिहास

1943 खारकोव की तीसरी लड़ाई शुरू हुई।
1959 साइप्रस की स्वतंत्रता के बारे में यूनान, तुर्की और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ।
1963 बेट्टी फ्रेडन की द फेमिनिन मिस्टिक, एक गैर-काल्पनिक किताब है, जिसे द अनटाइटेड स्टेट्स में सेकंड-वेव फेमिनिज्म की शुरुआत में स्पार्किंग के साथ प्रकाशित किया गया था।
1965 वियतनाम गणराज्य की सेना के कर्नल फाम नोक थोओ और उत्तर वियतनामी विएतनाम के एक कम्युनिस्ट जासूस के साथ, जेनरालस लैम वान फाट और ट्रान थिएन खीम ने गुयेन खान के विषयगत जुंटा के खिलाफ तख्तापलट का प्रयास किया।
1966 यूनाइटेड किंगडम के नौसैनिक मंत्री क्रिस्टोफर मेयू ने इस्तीफा दिया।
1986 सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मीर का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था, जिसने अंतरिक्ष में पहला दीर्घकालिक अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया।
1992 केन लुडविग के संगीतमय क्रेजी फॉर यू का प्रीमियर 19 फरवरी, 1992 को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। इसे 1622 के प्रदर्शन के लिए शटबर्ट थियेटर न्यूयॉर्क में उसी तिथि को खोला गया था।
1993 केन्या मूर, एक 22 वर्षीय लड़की माइक्रिगन को 19 फरवरी, 1993 को 42 वें मिस यूएसए के रूप में ताज पहनाया गया था।
1993 हैतो के पास समुद्र में 1500 यात्रियों सहित एक जहाज़ डूबा।
1997 चीन के वरिष्ठ नेता और देश में आर्थिक सुधार की नींव डालने वाले डेंग ज़ियाउ पेंग का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
1999 डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने वाशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई।
2003 ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की सैन्य उड़ान सिराक पर्वत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपदा में 275 लोग मारे गए थे।
2006 मेक्सिको के न्यूवा रोसेटा में एक कोयला खदान में एक मिथेन विस्फोट, 65 खनिक फंस गया और मारे गए।
2010 वेटिकन शहर ऑस्ट्रेलियाई मैरी मैक किलाप को 19 फरवरी, 2000 को विमुद्रीकरण के लिए अपने पहले संत के रूप में मंजूरी देता है।
2011 बेलितुंग शिपब्रेक (कटोरे चित्रित) से आइटम, तांग राजवंश कलाकृतियों का बड़ा संग्रह, जो एक स्थान पर पाया जाता है, सिंगापुर में प्रदर्शन पर रखा गया था।
2012 19 फरवरी, 2011 को ब्राजील के रियो कार्निवल, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के दौरान बोला बूटा अकड़ पार्टी में 2.2 मिलियन लोग शामिल हुए।

बांग्लादेश के साथ नयी शुरुआत की उम्मीद

प्रभु चावला

दक्षिण एशिया की ज्यामिति में भूगोल ही नियति है और स्मृति कभी जड़ नहीं होती। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी भर नहीं है, यह भारत की महाद्वीपीय सुरक्षा का पूर्वी आधार स्तंभ और उन साझा जल संसाधनों का संरक्षक है, जो आधे अरब जीवन को सींचते हैं। यह बंगाल की खाड़ी के विस्तृत होते रणनीतिक रंगमंच का प्रवेश द्वार भी है। इसलिए ढाका में जो कुछ भी घटित होता है, उसकी गूंज इसके डेल्टा मैदानी इलाकों से बहुत दूर तक जाती है।

पिछले सप्ताह बांग्लादेश ने एक ऐसा फैसला दिया, जिसकी गूंज भूकंपीय बदलाव की तरह थी। तारिक रहमान की बीएनपी ने चुनाव में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले 2024 के 'जेन जी' विद्रोह से जन्मा और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला अंतरिम प्रशासन अब इतिहास बन गया है। तीन दशकों से अधिक के महिला वर्चस्व के बाद एक पुरुष ढाका में प्रधानमंत्री पद संभाल रहा है।

कभी एक अनिच्छुक सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी अब लगभग 70 सीटों के साथ विपक्ष का नेतृत्व कर रही है। इसके बावजूद इस जनादेश का सही अर्थ तो कट्टरपंथी ताकत की करारी हार में ही निहित है, जो महज छह सीटें ही जीत पायी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नयी वास्तविकता स्पष्ट रूप से पहचानी है। नतीजा सामने आने के कुछ ही घंटों के भीतर तारिक रहमान को फोन कर बधाई देने वाले वह पहले शासनाध्यक्षों में से थे।

यह पहल एक लोकतांत्रिक, स्थिर और समावेशी बांग्लादेश के साथ काम करने की भारत की तत्परता को रेखांकित करती है। मीडिया विशेषज्ञों के लिए बांग्लादेश का यह घटनाक्रम शेख हसीना के बाद के अंतराल की बर्बरता की निर्मम राष्ट्रीय जांच, अल्पसंख्यकों की गरिमा पर एक बाध्यकारी जनमत संग्रह तथा आर्थिक सुधार, व्यावहारिक शासन और राष्ट्रीय नवीनीकरण पर केंद्रित 'बांग्लादेश फर्स्ट' सिद्धांत की एक गूंजती हुई पुष्टि है। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ आतंक के सुनियोजित शासन में डूब गया था।

वैश्विक संस्थानों ने पहले 100 दिनों में ही हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर 2,000 से अधिक हमले दर्ज किये थे, जिनमें हत्याएं, मंदिरों को जलाना और सुनियोजित निष्कासन शामिल थे, जिससे हजारों लोग भारत आने को मजबूर हुए। खुद मोहम्मद यूनुस द्वारा आमंत्रित एक संयुक्त राष्ट्र जांच समिति ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के अंतरिम शासन के इनकार को खारिज कर दिया और हिंदुओं, अहमदिया तथा कुछ स्वदेशी समूहों के खिलाफ लक्षित अभियानों की पुष्टि की। भारतीय स्क्रीन पर विस्थापित परिवारों, नष्ट किये गये मंदिरों और

शिकार होते श्रद्धालुओं के दृश्यों ने द्विपक्षीय संबंधों को आक्रोश की भट्टी में बदल दिया। भारत द्वारा बेदखल प्रधानमंत्री हसीना को शरण देने ने द्विपक्षीय दरार को और गहरा किया।

हालांकि, अपनी मां खालिदा जिया की मृत्यु के बाद लंदन से 17 साल के निर्वासन से लौटे तारिक रहमान ने खुद को संप्रभुता के रक्षक के रूप में पेश किया। एक संबोधन में उन्होंने राष्ट्र को पहाड़ियों और मैदानों, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों की एक साझा विरासत घोषित किया, और जोर दिया कि हर नागरिक को बिना डरे सड़कों पर चलना चाहिए। जमात के संभावित शासन के डर ने इस संदेश को पुरअसर बनाया। करीब तीन दर्जन हिंदू बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में, जो कभी अवामी लीग के गढ़ थे, नौ प्रतिशत हिंदू मतदाताओं ने निर्णायक रूप से बीएनपी का साथ दिया।

उन्होंने तारिक रहमान की पार्टी को उन नेटवर्कों के खिलाफ इकलौती सक्षम ढाल के रूप में देखा, जिन्होंने उन्हें 18 महीनों तक आतंकित किया था। बांग्लादेश के चुनावी नतीजे से एक असंभव गठबंधन बना। सुरक्षा चाहने वाले अल्पसंख्यक, गरिमा और नौकरियों की मांग करने वाले युवा तथा वंशानुगत शासन व पश्चिमी संरक्षण को खारिज करने वाले रूढ़िवादी मुसलमान एक साथ आ गये। इस्लामी चुनौती हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है। जमात और उसके सहयोगियों के पास 77 सीटों के साथ एक कठोर वैचारिक मशीनरी भी है। ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उन्होंने भारत की सीमा से लगे निर्वाचन क्षेत्रों में अपना सबसे मजबूत समर्थन हासिल किया, जिसके गंभीर निहितार्थ हैं।

इससे सीमापार घुसपैठ को प्रोत्साहन मिलने का जोखिम है। बीएनपी की जीत बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए एक नाजुक उम्मीद जगाती है। रहमान ने व्यवस्था बहाल करने और सभी धर्मों की सुरक्षा को राज्य के मुख्य कर्तव्य के रूप में स्थापित करने का वादा किया है। हिंदुओं के नरसंहार ने आपसी विश्वास को जख्मी कर दिया है। नयी दिल्ली ने घबराहट के साथ देखा कि कैसे दंगे फैले और शरणार्थी सीमा पार कर गये, जिससे संवेदनशील राज्यों में राजनीतिक तूफान पैदा हो गया।

शेख हसीना को मानवता के आधार पर दी गयी शरण को भारत को दुश्मन के रूप में चित्रित करने का हथियार बनाया गया। ठप पड़ी जल वार्ता से लेकर सांस्कृतिक बहिष्कार और पिछले महीने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय धरती पर मैच खेलने से इनकार के असाधारण निर्णय तक, संबंध पूरी तरह टूट गये। क्रिकेट का जो खेल कभी सेतु था, वह युद्ध का एक और मैदान बन गया। फिर भी, मोदी द्वारा रहमान के जनादेश की त्वरित मान्यता ने आपसी संबंधों के पुनर्गठन का एक द्वार खोल दिया है।

भारत के लिए, बांग्लादेश के नये नेतृत्व का आचरण निर्णायक कारक होगा। क्या तारिक रहमान अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, 2024-25 के अत्याचारों के लिए न्याय दिलायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश फिर कभी भारत विरोधी विद्रोहियों को पनाह नहीं देगा? उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा तक फैले व्यावहारिक साझेदारी का एक नया युग संभव है। भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य तीन अडिग शर्तों पर टिका होगा।

शुरुआत में, रहमान को चरमपंथी तत्वों से स्पष्ट रूप से संबंध तोड़ने होंगे और भारतीय उग्रवादियों को पनाह देने से इनकार करना होगा। इसके अलावा, ढाका को आपसी रणनीतिक और आर्थिक लाभ के आधार पर एक लेन-देन वाले संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए, तथा उस सीमापार टकराव को खारिज करना चाहिए, जिसने बार-बार संबंधों में जहर घोला है। दोनों राष्ट्र भूगोल, इतिहास और साझा नियति से इस तरह बंधे हैं, जिसे विचारधारा मिटा नहीं सकती। बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा कि वह अंतहीन टकराव के पाकिस्तान मॉडल को खारिज कर दे। भारत और बांग्लादेश के एक साथ आने से यह डेल्टा विकास, कनेक्टिविटी और स्थिरता के पावरहाउस के रूप में उभर सकता है।

विरोध नीतियों का हो व्यक्तियों का नहीं

विश्वनाथ सचदेव

नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के राहुल गांधी की भूमिका, विशेषकर उनके भाषणों को लेकर जहां एक ओर उनकी तीखी आलोचना होती है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। उनके चाहने वाले यह मानते हैं कि बीते हुए कल के राहुल गांधी और आज के नेता प्रतिपक्ष में बहुत अंतर आया है। यह भी सही है कि सत्ता-पक्ष, यानी भाजपा के सांसद उनकी भूमिका को लेकर अक्सर परेशान होते दिखते हैं। इस परेशानी का एक उदाहरण वह प्रस्ताव है जो भाजपा के एक 'प्रखर' कहलाने वाले नेता ने लोकसभा में रखा है।

नेता प्रतिपक्ष के आचरण की आलोचना करने वाला यह प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो राहुल गांधी को न केवल संसद की सदस्यता से वंचित होना पड़ेगा, अपितु जीवन भर भारत की संसद के सदस्य नहीं बन पाएंगे! हालांकि इस संदर्भ में अभी संशय बना हुआ है, पर यह सही है कि भाजपा के सांसद ने अपने प्रस्ताव में यह मांग रख कर सत्तारूढ़ पक्ष के इरादों को अवश्य उजागर कर दिया है।

यह सही है कि संसद या विधानसभाओं के सदस्य अपनी सोच, अपनी विचारधारा और अपनी मान्यताओं के आधार पर भी निर्वाचित होते हैं लेकिन विरोधी विचारधारा का मतलब एक-दूसरे का दुश्मन होना नहीं होता। हमारे विचार एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, हम पृथक नीतियों को मानने वाले हो सकते हैं। एक-दूसरे की नीति की आलोचना करना भी गलत नहीं है,

पर गलत यह तब हो सकता है जब आलोचना जरूरत से ज्यादा और अनावश्यक रूप से तीखी हो जाए। ऐसी कोई भी आलोचना एक-दूसरे के रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर दे तो उसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए, जब ऐसी कोई कोशिश होती दिखाई दे जिसमें पारस्परिक कटुता झलकती हो, तो ऐसी कोशिश करने वाले की नीयत पर शक होना स्वाभाविक है।

राहुल गांधी के खिलाफ 'सबस्टेंटिव मोशन' ऐसी ही कोशिश का एक उदाहरण लग रहा है। नेता विपक्ष के सवालों का जवाब नेता विपक्ष को ही मैदान से हटाना नहीं हो सकता। यह सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपनी नीतियों का औचित्य प्रमाणित करे। सरकार संसद के प्रति, और इसीलिए देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति जवाबदेह होती है।

जो सरकार जितनी जवाबदेही से अपना कर्तव्य निभाती है, वह उतनी ही जनतांत्रिक मानी जाती है। और जहां तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का सवाल है, उन्हें भी देश के मतदाता के प्रति अपना दायित्व निभाना होता है। हर प्रतिनिधि से परिपक्वता की अपेक्षा मतदाता करता है।

सदन में, और सदन के बाहर भी, निर्वाचित प्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी सजगता और ईमानदारी प्रमाणित करे। हमारे हर नेता को इस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करते दिखना होगा- तभी जनतंत्र सुरक्षित रहेगा।

बंगाल में 'दुर्गा आंगन', 'बाबरी मस्जिद' और 'घुसपैठिए' की राजनीति

शैलेश कुमार

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले धर्म ध्वजा फहराने की कवायद तेज हो गई है। आर.एस.एस. के सौ साल पूरा होने के अवसर पर राज्य भर में होने वाले ड्क्षहदू सम्मेलन को भाजपा हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के विशेष अवसर और चुनाव अभियान की तरह इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदुत्व के मोर्चे को भाजपा के लिए खुला नहीं छोड़ा है। पिछले दिसम्बर में कोलकाता के न्यू टाऊन में विशाल 'दुर्गा आंगन' का शिलान्यास करके उन्होंने हिंदू मतदाताओं को भाजपा के खेमे में खिसकने से रोकने की जो बड़ी पहल शुरू की थी, उसे बंगाली अस्मिता से जोडने के अभियान पर लगातार आगे बढ़ा रही हैं।

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास करके ममता के सामने एक नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है और भाजपा इसे भी भुनाने की कोशिश में जुट गई है। बंगाल की राजनीति में इस समय कई सवाल गूंज रहे हैं। क्या हिंदू सम्मेलन और हुमायूं कबीर के बहाने भाजपा राज्य के 70 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं को ममता के खिलाफ खड़ा कर पाएगी? क्या हुमायूं कबीर और अन्य मुस्लिम पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को बांटने में सफल हो पाएंगी? या फिर अल्पसंख्यकों की रक्षा और दुर्गा आंगन की मशाल लेकर ममता एक बार फिर से जीत का झंडा फहराने में सफल होंगी? ममता इस समय कई मोर्चों पर जूझ रही हैं। एस.आई.आर. यानी विशेष मतदाता सूची सर्वेक्षण में मुसलमानों और अत्यंत गरीब लोगों का नाम कटने के मुद्दे पर उनके कार्यकर्त्ता बूथ स्तर पर लड़ रहे हैं और वह खुद सुप्रीम कोर्ट तक हाजिरी लगा चुकी हैं। बिहार, जहां एस.आई.आर. की शुरुआत हुई या फिर अन्य राज्य, जहां यह प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां बंगाल जैसी जुझारू लड़ाई दिखाई नहीं दे रही। भाजपा का अभियान चार मुद्दों पर केंद्रित है। 'बंगाल में हिंदू खतरे में है', भाजपा का मुख्य अभियान इसी नारे पर केंद्रित है। बंगाली हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है।

बंगलादेश की सीमा से लगे कुछ जिलों, जहां मुस्लिम

आबादी 50 फीसदी या ज्यादा है, का उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि बंगाली हिंदू जल्दी ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बंगलादेश से अवैध घुसपैठ का शोर मचाकर हिंदुओं की चिंता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आर.जी. कार मैडीकल कालेज में एक डॉक्टर से बलात्कार का उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। चौथा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। शिक्षक भर्ती घोटाला जैसे मामले इसके उदाहरण के रूप में पेश किए जा रहे हैं। ममता सी.बी.आई. और ई.डी. जैसी केंद्र सरकार की एजैंसियों से सीधे टक्कर ले रही हैं।

चुनाव में हिंदू-मुस्लिम मुद्दा बन जाए तो भाजपा फायदे में रह सकती है। लेकिन ममता आसानी से ऐसा होने देने के मूड में नहीं हैं। लेकिन उनके सामने मुस्लिम वोटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की पहल से मुस्लिम मतदाताओं के बीच हुमायूं कबीर की लोकप्रियता बढ़ी है। वैसे हुमायूं मुसलमानों के कोई प्रतिष्ठित नेता नहीं रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने तृणमूल के टिकट पर जीता था। 2019 में वह भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ कर तीसरे नंबर पर रहे थे। टी.एम.सी. से निकाले जाने के बाद उन्होंने अलग जनता उन्नयन पार्टी (जे.यू.पी.) बना ली है और 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं।

एक अन्य मुस्लिम नेता नौशाद सिद्दीकी अपनी पार्टी इंडियन सैक्युलर फ्रंट (आई.एस.एफ.) को वाम दलों से समझौता करके चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश में हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ए.आई.एम.आई.एम. इस बार सौ से ज्यादा सीटों पर दाव खेलने की तैयारी में है। इसके अलावा भी 5-6 मुस्लिम नेता छोटी-छोटी पार्टियां बनाकर चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 30 प्रतिशत है। पिछले चुनावों में ममता को मुस्लिम मतदाताओं का एकतरफा समर्थन मिला था। इसके बूते पर ही उनके पास आज 223 सीटें हैं।

भाजपा की 65 सीटों पर जीत भी एक बड़ी बात थी क्योंकि बंगाल में भाजपा कभी भी मजबूत पार्टी नहीं थी। 2021 में सी.पी.एम. और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में 2, 2019 में 18 और 2024 में 12 सीटें मिली थीं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टी.एम.सी. को करीब 48 प्रतिशत और भाजपा को 38 प्रतिशत वोट मिला था। जाहिर है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने पर टी.एम.सी. की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए ममता अपना हिंदू कार्ड बहुत सावधानी से खेल रही हैं।

कोलकाता की सांस्कृतिक पहचान, चौरंगी से वी.आई.पी. रोड होकर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते में कई जगहों पर मैट्रो रेल का अधूरा काम दिखाई देता है। यह प्रोजैक्ट कई वर्षों से घिसट-घिसट कर चल रहा है। काम थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर महीनों तक रुक जाता है। बंगाल में अधूरे विकास की कहानी लगभग हर जिले में दिखाई देती है। टाटा के नैनो कार प्रोजैक्ट को राज्य से बाहर खदेड़ कर 2011 में सत्ता में आईं ममता बनर्जी 15 सालों में राज्य के विकास को पटरी पर नहीं ला पाई हैं। रोजगार के लिए पलायन करने वाले राज्यों में बंगाल शीर्ष पर है। कई राज्यों में उन्हें बंगलादेशी बताकर लगातार अपमानित और उत्पीड़ित किया जाता है। राज्य में रोजगार बढ़ नहीं रहा क्योंकि विकास के लिए राज्य के पास पैसा नहीं है। ममता इसके लिए भी केंद्र को दोषी ठहराती हैं। उनका आरोप है कि केंद्र उन्हें विकास के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दे रहा। पिछले साल 15 सालों में बंगाल की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। करीब तीस वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद सी.पी.एम. और वामपंथी दल इस तरह हाशिए पर पहुंचे कि 2021 के चुनावों में उनका खाता भी नहीं खुला। वाम दलों से पहले करीब 25 सालों तक सत्ता संभालने वाली कांग्रेस भी सिर्फ नाम के लिए बची है। भाजपा का उदय ममता के सत्ता में आने के बाद ही हुआ और सी.पी.एम. तथा कांग्रेस को पीछे धकेल कर राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बन गई।

अमरीका का ट्रम्प कार्ड और पाकिस्तान की छटपटाहट

ऋतुपर्ण दवे

अगर कहा जाए कि मौजूदा अमरीका के पास 'ट्रम्प कार्ड' है जो कब चल दे, कोई नहीं जानता, तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का तल्खी भरा कहें या दर्द भरा बयान यही बताता है। गत दिवस वह नैशनल असैंबली में अमरीका की पाकिस्तान के प्रति भूमिका पर बोलते समय कुछ ऐसा बोल गए, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान का अपने सामरिक हितों के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, उसके बाद टॉयलैट के पेपर जैसा छोड़ दिया। निश्चित रूप से इतना तो समझ आता है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में बेचैनी जरूर दिख रही थी। अन्दरूनी तौर पर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ और परेशान होगा, यह लगता नहीं था।

अमरीका ने इस्लाम को इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर अपना मतलब साध लिया और स्वार्थी पाकिस्तान समझते हुए भी अनजान बना रहा। जब भारत से अमरीका की चंद दिनों पहले की नजदीकी समझ आई तो दर्द छलकने लगा। पाकिस्तान अच्छे से समझता था कि अफगानिस्तान की जमीन पर लड़े गए दो युद्ध न तो इस्लाम के हित में थे न ही मजहब से प्यार करने वालों के। हकीकत में ये दुनिया का दारोगा कहलाने वाले अमरीका के स्वार्थ से जुड़े थे, जो वास्तव में एक सुपरपावर की रणनीतिक जंग थी। निश्चित रूप से अब लगने लगा है कि पाकिस्तान-अमरीका के बीच मुनीर और शहबाज शरीफ के चापलूसी भरे रिश्ते पर भी अमरीकी राष्ट्रपति का ट्रम्प कार्ड चल गया है। खिसियाए पाकिस्तान और उसके रक्षा मंत्री के बयान के बाद, अब अंतर्राष्ट्रीय मायने चाहे जो निकाले जाएं लेकिन यह समझ आने लगा है कि पाकिस्तान की स्थिति 'उगलत लीलत पीर घनेरी' जैसी हो गई है, जाए तो जाए कहां? हालांकि ख्वाजा आसिफ अब मानते हैं कि पाकिस्तान ने सोवियत संघ के खिलाफ और 2001 के बाद अमरीका के नेतृत्व वाले युद्धों में भाग लिया था जो धार्मिक जेहाद

कतई नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह राजनीतिक लाभ और दुनिया की बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करने बाबत था।

आर्थिक रूप से टूट चुके और एक तरह से आंतरिक युद्ध के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को पहले ही समझना था कि ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। बहरहाल मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ट्रम्प की चापलूसी कर-कर के बनाए गए संबंधों में न केवल कड़वाहट आ रही, बल्कि कीड़े भी पड़ रहे हैं। शायद पाकिस्तान यह भूल गया है कि अच्छा पड़ोसी उसका सही हितैषी होता है। लेकिन उसने तो शुरू से भारत को अपना दुश्मन मान रखा था, जिसके नतीजे अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान खुद ही अपने बुने जाल में फंस कर कैसे फडफ़ड़ा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसी से समझ आती है कि उसके मौजूदा हुक्मरान खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। अब आसिफ द्वारा की गई आलोचना उनकी छाती पीटने वाली मानसिक स्थिति जैसी है। वे इतने परेशान और व्यग्र हैं कि पूर्व सेना प्रमुखों जनरल जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ की खुलकर आलोचना करते हुए यह कहने से भी नहीं हिचकते कि दोनों ने अमरीका को अफगानिस्तान युद्ध के लिए अपना पोर्ट और एयरस्पेस देकर दोगलई की। दोनों ने इस लड़ाई की खातिर अपनी रीति-नीति भी बदल दी, जिसे आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अब आसिफ को अफगानिस्तान की तबाही याद आने के साथ-साथ खुद की गलतियां भी नजर आने लगी हैं, जिसके चलते न केवल लाखों लोग प्रभावित हुए, तबाह हुए, बल्कि पीढियां भी बर्बाद हुईं। वे इसे पाकिस्तान का 'यूज एंड थ्रो' बताते हुए यहां तक कहते हैं कि हकीकत में यह किराए का एक युद्ध था, जिसमें पाकिस्तान का अमरीका ने अपने सामरिक हितों के लिए खासा इस्तेमाल किया और मतलब निकलते ही छोड़ दिया। यकीनन टुकड़े फैंक कर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया।

क्या यह सब भारत के साथ हुई डील के बाद पाकिस्तान को समझ आया? पाकिस्तान जब झोली लेकर भीख मांगते हुए अमरीका के सामने खड़ा होता था, तब यह पुरानी बातें याद क्यों नहीं रहती थीं? जब तक उसकी झोली में अमरीकी डॉलर बतौर भीख आते रहे तो मुंह बंद रहता था। तब भी क्या पाकिस्तान इतना अनजान था? अमरीका की भारत के प्रति नरमी कहें या नए व्यावसायिक क्षेत्र में साथ आने का इशारा, उससे भी पाकिस्तान परेशान है। इधर अमरीका ने दक्षिण एशिया और पश्चिमी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, जो ड्क्षहद महासागर और प्रशांत महासागर को जोडने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री और भू-राजनीतिक क्षेत्र है और अफ्रीका के पूर्वी तट से अमरीका के पश्चिमी तट तक फैला है, को लेकर जैसे ही भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया, पाकिस्तान को मानो सांप सूंघ गया। पाकिस्तान को डर क्यों लगा क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग और 65 प्रतिशत आबादी वाला क्षेत्र है, जो आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी एक-एक गलती याद आ रही है। उसके कई नेता इस बात पर छाती पीटते दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान किन नीतियों से तबाह हुआ! अब वहां संसद में खुलेआम स्वीकारा जा रहा है कि दुनिया अनजान बनकर नहीं रह सकती। निश्चित रूप से पाकिस्तान-अमरीका संबंध एक खतरनाक मोड़ पर हैं। देर आयद दुरुस्त आयद का अलाप पाकिस्तान कब तक अलापेगा और इससे होगा क्या? दुनिया जानती है कि डोनॉल्ड ट्रम्प बतौर ट्रम्प कार्ड कब कौन सी चाल चल जाएं, कोई नहीं जानता!

दो अलग-अलग मौके, 2 नेता: 1 संदेश!

हरीश गुप्ता

अगर किसी को लगता था कि 75 की जादुई उम्र के साथ रिटायरमेंट केक और एक औपचारिक विदाई समारोह आता है, तो पिछले सप्ताहांत ने उन्हें हकीकत का सामना करवाया- दो चरणों में, पहले दिल्ली और फिर मुंबई में। 7 फरवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' के बीच में उम्र बढ़ने से जुड़ा एक हल्का-फुल्का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उनके 75वें जन्मदिन पर एक नेता ने फोन किया और मजाक में कहा, ''तो, अब आप 75 साल के हो गए हैं?'' मोदी ने हमेशा की तरह हंसमुख अंदाज में और स्पष्ट इरादे के साथ जवाब दिया: ''मेरे पास अभी भी 25 साल बाकी हैं।'' किसी और संदर्भ में, यह महज हास्य हो सकता था। लेकिन भारतीय राजनीति में, यह एक संक्षिप्त सार्वजनिक सूचना के समान था। 'सेवानिवृत्ति नियमों' और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच, मोदी का यह हास्य एक संदेश बनकर उभरा: अभी विदाई भाषण लिखना शुरू न करें। फिर, मानो तय समय पर, 8 फरवरी आ गई। मुंबई में, आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने उम्र और अधिकार के बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा- आम तौर पर कहा जाता है कि 75 वर्ष की आयु के बाद किसी को कोई पद धारण किए बिना काम करना चाहिए, लेकिन संघ ने उन्हें काम जारी रखने के लिए कहा है। और जब भी आरएसएस निर्देश देगा, वे पद छोड़ देंगे। दो दिन, दो नेता, एक ही आयु सीमा और आश्चर्यजनक रूप से समान संदेश: उम्र भले ही 75 हो, लेकिन पद छोड़ने का रास्ता अपने आप नहीं खुलता। शायद यह एक संयोग था। या फिर राजनीतिक जगत सबको याद दिला रहा था कि इस व्यवस्था में सेवानिवृत्ति जन्मदिन पर निर्भर नहीं होती, बल्कि समय से जुड़ी होती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मेरे पास अभी 25 साल बाकी हैं', तो यह जन्मदिन पर किए गए मजाक जैसा लगा। दर्शक हंस पड़े। कैमरे क्लिक करने लगे। लेकिन भाजपा के महत्वाकांक्षाओं से भरे प्रतीक्षा-कक्ष में कहीं न कहीं हंसी

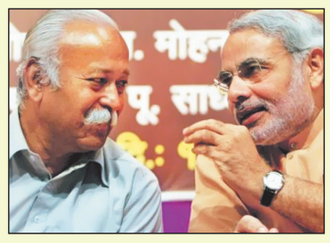

थम सी गई। क्योंकि राजनीति में, मजाक अक्सर एक छिपी हुई घोषणा होती है। वर्षों से, दिल्ली के भगवा गलियारे सावधानीपूर्वक तैयारियों से भरे रहे हैं - वरिष्ठ नेता समयसीमा का आकलन कर रहे थे, युवा चेहरे अपनी प्रस्तुति को आकर्षक बना रहे थे, और आशावान नेता चुपचाप शीर्ष कुर्सी के सपने देख रहे थे। कुछ ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, कुछ ने अधीरता से, सभी इस बात से आश्वस्त थे कि राजनीति का स्वाभाविक क्रम उत्तराधिकार है। फिर आया मोदी का गणित। 75, और 25, आपको 2047 से आगे ले जाते हैं - वही वर्ष जिसे वे बार-बार विकसित भारत के लक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। अचानक, नारे में तीक्ष्णता आ गई। शायद यह केवल भारत की विकास यात्रा के बारे में नहीं था। शायद यह मोदी के व्यक्तिगत राजनीतिक रोडमैप के बारे में भी था। संदेश, जानबूझकर हो या अनजाने में, स्पष्ट था: मोदी-बाद के युग के लिए अभी से तैयारी शुरू न करें। अनुभवी नेताओं के लिए यह एक बड़ा झटका था-जिस विदाई की वे उम्मीद कर रहे थे, वह शायद कभी तय समय पर न आए। युवा नेताओं के लिए तो यह और भी परेशान करने वाला था। उनकी आकांक्षाएं, जो कभी शांत भाव से पनप रही थीं, अब एक अनिश्चित परिपक्वता तिथि वाले दीर्घकालिक निवेश की तरह लग रही थीं। भाजपा में महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होती-बस कुछ समय के लिए टल जाती है। इसलिए जब देश सेवानिवृत्ति के नियमों पर बहस कर रहा है, पार्टी कार्यकर्ता अगले चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है : मोदी के '25 साल' वाले बयान ने सिर्फ समय सीमा को ही नहीं बढ़ाया। इसने प्रतीक्षारत सभी लोगों के धैर्य-और राजनीतिक भविष्य-को भी परख लिया।

नेचुरोपैथी में बनाएं अपना कॅरियर

एक नेचुरोपैथ यानी प्राकृतिक चिकित्सक का वेतन काफी हद तक उसकी लोकेशन, विशेषज्ञता, योग्यता और अनुभव पर निर्भर करता है। वैसे शुरूआती तौर पर एक नेचुरोपैथ दस हजार से बीस हजार रूपए आसानी से कमा सकता है। एक बार अनुभव प्राप्त करने के बाद आपको आकर्षक वेतन मिल सकता है।

आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल जिस तरह का है, उसके कारण हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहता ही है। लेकिन हर समस्या के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना उचित नहीं माना जाता। अगर आप भी लोगों का इलाज प्राकृतिक तरीके से करने में विश्वास रखते हैं तो नेचुरोपैथी में अपना भविष्य बना सकते हैं। यह एक ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा है, जिसमें प्रकृति के पांच तत्वों की सहायता से व्यक्ति का इलाज किया जाता है। यह इलाज की एक बेहद पुरानी पद्धति है।

स्किल्स

इस क्षेत्र में कॅरियर देख रहे व्यक्ति को सामान्य चिकित्सा व मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सफल नेचुरोपैथ बनने के लिए आपके भीतर धैर्य, कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल्स, आत्मविश्वास, मरीज की जरूरतों को समझना, मोटिवेशनल्स स्किल्स व रोगियों के भीतर विश्वास पैदा करने का भी कौशल होना चाहिए।

क्या होता है काम

एक नेचुरोपैथ का मुख्य काम सिर्फ रोगी का इलाज करना ही नहीं होता, बल्कि वह अपने पेशेंट के खानपान और उसके लाइफस्टाइल में भी बदलाव करता है, ताकि व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो सके। इतना ही नहीं, एक नेचुरोपैथ को मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वह रोगी की स्थित कि को समझकर उसे बेहतर उपचार दे सके।

योग्यता

इस क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों का भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में कम से कम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके बाद आप बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल हैं।

संभावनाएं

एक नेचुरोपैथ वेलनेस सेंटर्स, न्यूटिशन सेंटर, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर आदि में जॉब तलाश सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एकेडमिक्स, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस केयर, सोशल वेलफेयर, मैन्युफैक्चरिंग और नेचुरल प्रॉडक्ट्स कंपनी आदि में भी काम कर सकते हैं। भारत में प्राकृतिक चिकित्सक सरकारी और निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त किए जाते हैं। वैसे लग्जरी होटल व हेल्थ रिसॉर्ट में भी नेचुरोपैथ सर्विसेज दी जाती हैं, वहां पर भी जॉब की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न अखबार, मैगजीन में लिख सकते हैं या फिर खुद का यूट्यूब चैनल चलाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। एक अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक खुद का सेंटर भी खोल सकता है।

आमदनी

एक नेचुरोपैथ यानी प्राकृतिक चिकित्सक का वेतन काफी हद तक उसकी लोकेशन, विशेषज्ञता, योग्यता और अनुभव पर निर्भर करता है। वैसे शुरूआती तौर पर एक नेचुरोपैथ दस हजार से बीस हजार रूपए आसानी से कमा सकता है। एक बार अनुभव प्राप्त करने के बाद आपको आकर्षक वेतन मिल सकता है।

प्रमुख संस्थान

- इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली।
- महर्षि पतंजलि इंस्टीटयूट फॉर योगा नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च, गुजरात।
- बोर्ड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेरठ।
- सीएमजे यूनिवर्सिटी, मेघालय।
- प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रांची।
- एसडीएम कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा सांइस, कर्नाटक।
- हिमालयन यूनिवर्सिटी, ईटानगर।
- महावीर कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योग, छत्तीसगढ़।

एक टैटू आर्टिस्ट का काम महज टैटू बनाना ही नहीं होता। वह सबसे पहले अपने क्लाइंट की जरूरत को समझता है और उसके अनुसार अपने क्लाइंट को कुछ बेहतरीन सुझाव देता है। अंत में वह टैटू बनाता है।

अगर आपको भी है टैटू बनाने का पैशन...

पिछले कुछ समय से टैटू बनवाने का क्रेज युवाओं में काफी बढ़ गया है। वैसे तो टैटू पुराने समय से बनाए जाते रहे हैं लेकिन कुछ सालों से इसके स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े-बड़े स्टार्स भी बॉडी पर टैटू बनवाते हैं, फिर चाहे बात दीपिका पादुकोण की हो या प्रियंका चोपड़ा की, हर कोई टैटू बनवा चुकी है। आज के समय में बहुत से ऐसे युवा हैं जो न सिर्फ टैटू बनवाने का क्रेज रखते हैं, बल्कि वह टैटू बनाना भी सीखना चाहते हैं। अगर आपको भी टैटू बनाने का पैशन है तो आप इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं देख सकते हैं-

क्या होता है काम

एक टैटू आर्टिस्ट का काम महज टैटू बनाना ही नहीं होता। वह सबसे पहले अपने क्लाइंट की जरूरत को समझता है और उसके अनुसार अपने क्लाइंट को कुछ बेहतरीन सुझाव देता है। अंत में वह टैटू बनाता है। इसके अलावा टैटू बनाने के बाद शुरूआत में स्किन की सही तरह से केयर करनी भी जरूरी होती है, इसलिए एक टैटू मेकर का काम है कि वह अपने क्लाइंट को स्किन केयर के बारे में भी सारी जानकारी दे ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े।

स्किल्स

इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है आपका क्रिएटिव माइंड। आज के समय में पहले की तरह सिंपल टैटू नहीं बनाए जाते। इसलिए एक टैटू मेकर क्लाइंट की जरूरत को समझकर और अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अलग-अलग कलर कॉम्बीनेशन और केमिकल्स के जरिए बेहतरीन आकृति को उकेरता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में आपकी सफलता आपका पैशन तय करता है। अगर आप इस काम से दिल से प्यार करते हैं, तभी आपको इस क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक टैटू मेकर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। उसे लेटेस्ट ट्रेंड की जानकारी होनी चाहिए। एक टैटू बनाना देखने में भले ही आसान लगे लेकिन यह एक कठिन काम है। इसमें आपको बेहद पेशेंस और एकाग्रता की जरूरत होती है। कई बार लोगों को टैटू से त्वचा में संक्रमण भी फैल जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप इससे भी अच्छी तरह वाकिफ हों और हर तरह की सावधानी बरतते हुए ही अपना काम करें।

योग्यता

इस क्षेत्र में कॅरियर की संभावनाएं देख रहे छात्रों के लिए कोई मिनिमम योग्यता निर्धारित नहीं है। लेकिन टैटू बनाने में आजकल मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए आप किसी टैटू स्टूडियो या संस्थान से शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए टैटू मेकिंग सीख सकते हैं। यह कोर्स एक से दो महीने का होता है।

संभावनाएं

एक टैटू मेकर के लिए काम की कोई कमी नहीं है। टैटू मेकिंग का काम सीखने के बाद आप घर से ही काम की शुरूआत कर सकते हैं। अगर आप बजट अच्छा है तो अलग से टैटू मेकिंग स्टूडियो भी खोला जा सकता है। अगर आप क्लाइंट के घर जाकर काम कर सकते हैं तो ऑनलाइन काम को प्रमोट करना अच्छा रहेगा। इससे आपको कम समय में ही अच्छा काम मिलने लगेगा। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े मॉल्स में भी टैटू मेकिंग का काम शुरू किया जा सकता है।

आमदनी

इस क्षेत्र में कमाई अनुभव और आपके काम के अनुसार बढ़ती है। वैसे कोर्स करने के बाद शुरूआती दौर में एक टैटू मेकर प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपए आसानी से कमा सकता है। लेकिन कुछ सालों के अनुभव के बाद जब आप अपना नाम स्थापित कर लेते हैं तो आपकी आमदनी लाखों में भी हो सकती है।

कम्युनिकेशन डिजाइनिंग से दें कॅरियर को एक नई उड़ान

कम्युनिकेशन डिजाइन से संबंधित इस कोर्स की अवधि चार वर्ष है। इस कोर्स के दौरान छात्रों में ऐसी समझ का विकास किया जाता है, जिससे खुले और निर्मित स्थानों में संचार के लिए सही परिवेश की स्थापना हो सके। इसके साथ ही ऐसे अनुभवों का निर्माण हो सके जिनके समर्थन से दर्शकों के समक्ष विचारों की व्याख्या हो सके। देश के प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान डिजाइनिंग संबंधी कई कोर्स संचालित करता है। इन कोर्सेस में दाखिला लेकर छात्र न सिर्फ अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, बल्कि सफलता की नई कहानी भी लिख सकते हैं। आज हम आपको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में संचालित विभिन्न कोर्सो की जानकारी दे रहे हैं

बैचलर ऑफ डिजाइन बी.डेस

यह चार वर्षीय पाठ्यक्रम है जो आठ विषयों में उपलब्ध है। 12वीं स्तर के 20 वर्षीय विद्यार्थी इन कोर्सेस में दाखिला ले सकते हैं।

एनीमेशन फिल्म डिजाइन

कम्युनिकेशन डिजाइन से संबंधित इस कोर्स की अवधि करीबन चार वर्ष की होती है और इसमें महज 15 सीटें ही एनआईडी में उपलब्ध होती हैं। इस कोर्स को करने के बाद छात्र विभिन्न टीवी चैनल में एनिमेटर, करैक्टर डिजाइनर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोडूसर, कंसलटेंट आदि के रूप में काम कर सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।

सिरामिक एवं ग्लास डिजाइन

सिरामिक एवं ग्लास डिजाइन कला और रचनात्मकता के क्षेत्रों में शिल्प, वास्तु, चिकित्सा, सत्कार, सज्जा उत्पादों आदि शैलियों में कार्यात्मक सम्भावनायें भी प्रदान करता है। एनआईडी का यह विभाग भारतीय कला और शिल्प से प्रेरणा लेता है और छात्रों को भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन और नयी तकनीकों की क्षमता को समझने में मदद करता है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र एनज़ीओ, डिजाइन स्टूडियो, शिल्प उद्योग में भी रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं या खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।

एक्सबिशन डिजाइन

कम्युनिकेशन डिजाइन से संबंधित इस कोर्स की अवधि चार वर्ष है। इस कोर्स के दौरान छात्रों में ऐसी समझ का विकास किया जाता है, जिससे खुले और निर्मित स्थानों में संचार के लिए सही परिवेश की स्थापना हो सके। इसके साथ ही ऐसे अनुभवों का निर्माण हो सके जिनके समर्थन से दर्शकों के समक्ष विचारों की व्याख्या हो सके।

फिल्म व वीडियो कम्युनिकेशन

फिल्म व वीडियो कम्युनिकेशन कोर्स के तहत छात्रों को छोटी एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल, एंटरटेनिंग व मार्केट कम्युनिकेशन संबंधी शार्ट फिल्में बनाने करने के लिए तैयार किया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र ऑडियो-विजुअल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे छात्रों के लिए एड एजेंसी, फिल्म प्रॉडक्शन हाउस, टीवी चैनल्स व अन्य कई सरकारी क्षेत्रों व एनजीओ के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं।

फर्नीचर डिजाइन

फर्नीचर डिजाइन भी वास्तव में एक कला है और इस कला की पूरी जानकारी एनआईडी के चार वर्षीय फर्नीचर डिजाइन कोर्स से प्राप्त होती है। कोर्स में विभिन्न प्रकार के मैटीरियल, उनके इस्तेमाल और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

ग्राफिक डिजाइन

पिछले कुछ समय से ग्राफिक डिजाइनर की मांग काफी बढ़ी है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक लोग ग्राफिक्स का सहारा लेने लगे हैं। इसके जरिए चीजों को आसानी से समझा जा सकता है और यही कारण है कि यह कोर्स छात्रों के बीच खासा पसंद किया जाता है।

जीडीजीपी (ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन डिजाइन)

4 वर्ष का यह कोर्स विजयवाड़ा और कुरुक्षेत्र में उपलब्ध है। इसमें छात्रों का 12वीं पास होना आवश्यक है और उम्मीदवार की आयु 20 से अधिक न होनी चाहिए।

प्रॉडक्ट डिजाइन

प्रॉडक्ट डिजाइन उन वस्तुओं की रचना करना है, जो लोगों के लिए फायदेमंद है। वस्तुए बड़ी व्यवस्था का मुख्य अंश होती है। कोर्स के दौरान प्रोजेक्ट्स का मुख्य केंद्र उपयोगकर्ताओं की जरूरत, उत्पाद और आर्थिक प्रभाव के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर रहता है।

टेक्सटाइल डिजाइन

टेक्सटाइल डिजाइन के कोर्स के तहत छात्रों के भीतर कपड़ा अथवा टेक्सटाइल की समझ का ज्ञान विकसित किया जाता है। इस कोर्स की अवधि चार वर्ष है।

स्नातकोत्तर डिजाइन (एम.डेस)

किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त छात्र इस कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 वर्ष की अवधि का यह कोर्स अहमदाबाद, बेंगलुरु और गांधीनगर कैंपसों में उपलब्ध है। इन कोर्सेस में दाखिला लेने वाले आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कोर्स लगभग 19 विषयों में उपलब्ध है, जो इस प्रकार है-

- ऐनीमेशन फिल्म डिजाइन
- अपैरल डिजाइन
- सिरामिक व ग्लास डिजाइन
- डिजाइन फॉर रिटेल एक्सपीरियंस
- डिजिटल गेम डिजाइन
- फिल्म व वीडियो कम्यूनिकेशन डिजाइन
- फर्निचर डिजाइन
- ग्राफिक डिजाइन
- इन्फोरमेशन डिजाइन
- इंटरैक्शन डिजाइन
- लाइफस्टाइल ऐक्सेसरी डिजाइन
- न्यू मीडिया डिजाइन
- फोटोग्राफी डिजाइन
- प्रोडक्ट डिजाइन
- स्ट्रैटिजिक डिजाइन प्रबंधन
- टेक्सटाइल डिजाइन
- टॉय ऐंड गेम डिजाइन
- ट्रांसपोर्टेशन व ऑटोमोबाइल डिजाइन
- यूनिवर्सल डिजाइन

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली में पीएम मोदी से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई

नईदिल्ली। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बुधवार को दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, क्योंकि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। वे इस बड़े इवेंट में शामिल होने के लिए यहां आए हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक, वे 20 फरवरी को एक कीनोट स्पीच देंगे। देश में आने के कुछ ही समय बाद, पिचाई ने एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट किया कि वे वापस आकर खुश हैं और उन्होंने सभी को गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। दुनिया भर से कई पॉलिसीमेकर, ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर, स्टार्टअप, एआई रिसर्चर, एकेडेमिशियन, इनोवेटर, हेल्थकेयर लीडर और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि अपने इनोवेशन शेयर करने के लिए आए हैं। इसमें 110 से ज़्यादा देश और लगभग 30 इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई हेड ऑफ़ स्टेट और मिनिस्टर शामिल हैं।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा एनडीए

चेन्नई। तमिलनाडु में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच राजनीतिक सूत्रों के अनुसार चुनावों से पहले गहन प्रचार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्च में दो बार तमिलनाडु का दौरा करने की उम्मीद है। इस महीने के अंत में चुनाव आयोग तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। तमिलनाडु में, एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (एआईएडीएमके) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) अपने गठबंधन ढांचे को मजबूत करने के अंतिम चरण में है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) और पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) जैसे प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों ने पहले ही एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन कर लिया है, जिससे राज्य में एनडीए की स्थिति मजबूत हो गई है।

10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का एलान

नई दिल्ली। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीख का एलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे। इनमें महाराष्ट्र की सात, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। वहीं ओडिशा की चार, तमिलनाडु की छह, असम की तीन, छत्तीसगढ़ की दो, हरियाणा की दो, तेलंगान की दो और हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके मुताबिक 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च को नामांकन भरे जाएंगे और 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और 16 मार्च को ही वोटों की गिनती होगी। 20 मार्च 2026 से पहले चुनाव पूरा होना है।

मायावती ने यूपी विस चुनाव अकेले लड़ने का किया एलान

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इन दिनों लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती प्रदान करने के बजाय अर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) को सफलता की कुंजी बताने की स्वार्थी चर्चाएं चल रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यूपी में जैसे-जैसे चुनाव पास आएंगे, जो लोग हमारे खिलाफ हैं, वे हमें सत्ता से दूर रखने की और भी कोशिश करेंगे। हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। सिर्फ यूपी में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सभी अंबेडकरवादियों को बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का आत्म-सम्मान पाने के आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा के यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने की बात फेक न्यूज है। यह बिल्कुल गलत, झूठ, हवा-हवाई व मनगढ़ंत है। बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाए सरकार के काम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को राज्य की शक्ति का प्रतीक बताया, जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क सहित तीव्र अवसंरचना विकास और माफिया तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बुलडोजर और ब्रह्मोस एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर उन लोगों की इच्छाशक्ति को दर्शाता है जो राज्य में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में यूपी सीएम ने इसे भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बताया। विरोधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास करता है, तो देश निर्णायक जवाब देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की।

असम कांग्रेस में घमासान : भूपेन बोराह का अपमान वाला इस्तीफा

ये भाजपा में जाने के बहाने हैं : गौरव गोगोई

गुवाहाटी। असम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नए सिरे से उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व एपीसीसी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोराह ने पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। बोराह ने सोमवार को कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिससे पूरे राज्य में राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया। उनकी घोषणा के तुरंत बाद, कुछ स्थानीय पार्टी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की थी और अपने फैसले पर पुनर्विचार किया था।

हालांकि, हालिया घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि बोराह ने वास्तव में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की संभावना है। असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस कदम को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर अपने नए हमले में बोराह ने कहा कि उन्होंने पार्टी को अपने 32 साल दिए, लेकिन गौरव गोगोई के हाथों कई मौकों पर उनका अपमान किया गया। बोराह ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को भी इस बारे में बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी को 32 साल दिए। कांग्रेस ने मुझे विधायक से एपीसीसी अध्यक्ष बनाया। जब मैं 2021 में अध्यक्ष बना, तब कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन में थी। मैंने गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद, इंडिया गठबंधन बनने से पहले, मैंने 16 पार्टियों के साथ गठबंधन किया। उपचुनाव में तय हुआ था कि एक सीट सीपीआई (एमएल) को मिलेगी, लेकिन अचानक उसी रात एक ऐसे व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया गया जो कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं रहा था। गौरव गोगोई वह सीट नहीं जीत सके। 9 फरवरी को गठबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। मुझसे फिर से गठबंधन बनाने को कहा गया, मैंने बातचीत शुरू की।

उन्होंने दावा किया कि 11 तारीख को गौरव गोगोई ने कहा, आप अकेले मत जाइए, रकीबुल हुसैन को भी साथ ले जाइए... मैं सभी पार्टियों से बात कर रहा था, लेकिन 13 तारीख को गौरव गोगोई ने घोषणा की कि भूपेन बोराह ने गलतफहमी पैदा की है। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने सबके सामने मुझे क्यों अपमानित किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया... मैंने राहुल गांधी से भी कहा कि मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपमान हुआ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा।

इस विवाद पर बोलते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि बोराह भाजपा में शामिल होने के बहाने बना रहे थे। गोगोई ने कहा कि जब भी कोई भाजपा में शामिल होता है, उसे एक स्क्रिप्ट दी जाती है और उससे उसी के अनुसार बोलने की उम्मीद की जाती है। असम के लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी के भीतर ही समस्याएँ थीं, तो आपने किसी ऐसी पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए जो वास्तव में भाजपा के खिलाफ लड़ रही है? भाजपा का विरोध करने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं। आपने इस्तीफा देने के ठीक एक दिन के भीतर हिमंता बिस्वा सरमा से हाथ क्यों मिलाया?

असम विस से कांग्रेस ने किया वॉकआउट, दल-बदल के दो विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग

कांग्रेस ने बुधवार को असम विधानसभा से वॉकआउट किया। इसके साथ ही रायजोर दल में शामिल हुए अपने दो विधायकों की अयोग्यता की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता देबब्रता सैकिया ने अध्यक्ष से कांग्रेस द्वारा दोनों विधायकों के खिलाफ दायर दो नोटिसों पर फैसला मांगा। अब्दुर राशिद मंडल और शेरमन अली अहमद, जिन्हें पहले कांग्रेस ने निलंबित किया था। इसके बाद वे अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले रायजोर दल में शामिल हो गए थे। दोनों पश्चिमी असम के निर्वाचन क्षेत्रों से तीन बार विधायक रह चुके हैं। स्पीकर बिस्वजीत डाइमरी ने कहा कि उन्हें अभी-अभी नोटिस मिले हैं। उन्हें इन्हें पढ़ने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दोनों विधायकों को निष्कासित नहीं किया। लेकिन उसे उम्मीद थी कि अध्यक्ष उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर देंगे। चूंकि अध्यक्ष ने नोटिसों पर कोई फैसला देने से इनकार कर दिया। इसलिए कांग्रेस ने प्रश्नकाल की पूरी अवधि के लिए सदन से वॉकआउट कर दिया।

कांग्रेस में गांधीवादी विरुद्ध राहुलवादी की जंग?

मणिशंकर अय्यर के बयान पर रिजिजू का तीखा वार

नईदिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के राहुलवादी नहीं वाले बयान के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। अय्यर के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि वे गांधीवादी, नेहरूवादी, राजीववादी हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं, रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, जिसका नेतृत्व कभी परिपक्व नेताओं ने किया था, अब राहुल गांधी जैसी हो गई है और उनके आसपास के लोग भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने लगातार तीन हार के बाद भी उसी नेता को बनाए रखने पर आश्चर्य व्यक्त किया।

मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस में मजबूत नेता हुआ करते थे, जिनके भाषण और कार्यों में परिपक्वता होती थी। लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस राहुल गांधी जैसी हो गई है और उनके आसपास के लोग भी उन्हीं की तरह हो गए हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कांग्रेस इस तरह हो जाएगी: लगातार तीन बार हारने के बाद भी उसी नेता को बनाए रखेगी। भाजपा का कोई नेता तीन बार हारने के बाद नेता नहीं रह सकता।

अय्यर की ये टिप्पणियां आगामी केरल विधानसभा चुनावों पर उनकी टिप्पणियों से उपजे राजनीतिक विवाद के बीच आई हैं। अय्यर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की, हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की जीत को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि एक कांग्रेसी होने के नाते, मैं यूडीएफ को सत्ता में देखना चाहता हूं। एक गांधीवादी होने के नाते, मैं सच कह रहा हूं कि पिनारयी सरकार की शानदार उपलब्धियों के बाद, वाम सरकार का सत्ता में आना तय है।

उन्होंने आगे कहा कि केरल के मतदाता भारत के किसी भी अन्य देश के मतदाताओं की तुलना में सबसे बुद्धिमान और सबसे स्वतंत्र विचारक हैं। इसलिए, मैं यूडीएफ को सत्ता में देखना चाहता हूं, लेकिन एक गांधीवादी होने के नाते, जिसे सच बोलना चाहिए, मुझे एलडीएफ के अलावा किसी और के सत्ता में आने की संभावना नहीं दिखती। अय्यर की टिप्पणियों ने विवाद को जन्म दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया और कहा कि अय्यर पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। इस पर अय्यर ने कहा कि राहुल गांधी यह भूल गए हैं कि मैं पार्टी का सदस्य हूं। इसलिए, मैं गांधीवादी हूं। मैं नेहरूवादी हूं। मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं।

भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप

कर्नाटक में करोड़ों रुपये की जमीन बेहद कम दाम में गांधी परिवार को दी गई

बेंगलूरू। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर एक और जमीन घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में करोड़ों रुपये के नगर निगम के प्लॉट बेहद कम दाम पर कांग्रेस भवन ट्रस्ट को दे दिए गए हैं। भाजपा नेता और पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए।

भाजपा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर लगाए आरोप

गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय है, गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ सरकारी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है, जैसा कि हमने नेशनल हेराल्ड केस में देखा है, इसलिए कांग्रेस को हड़पू परिवार कहा जाए, तो यह गलत नहीं होगा।

नेशनल हेराल्ड केस में हमने देखा था कि कांग्रेस ने किस तरह से सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बना लिया। इसी तरह रॉबर्ट वाड्रा, किसानों की जमीन हड़पकर उस पर निजी व्यवसाय करते हैं।

भाजपा नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का सरकारी जमीन से जो प्यार है, वह इस हद तक बढ़ गया है कि कर्नाटक में करीब दो दर्जन सरकारी जमीनें, जिनका उपयोग कर्नाटक की जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाने के रूप में होना था, अब जनहित में इस्तेमाल नहीं हो रही हैं।

इन जमीनों का उपयोग कांग्रेस भवन बनाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने निगम प्रशासन के 12 प्लॉट कांग्रेस भवन ट्रस्ट को दे दिए हैं।

इसके साथ ही शहरी विकाश मंत्रालय के 12 और प्लॉट भी कांग्रेस भवन ट्रस्ट को सौंप दिए गए हैं। इन जमीनों की कुल कीमत 40-50 करोड़ रुपये बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस को ये प्लॉट सिर्फ 2 करोड़ रुपये में दे दिए गए हैं।

भाजपा ने कहा, कीमती सरकारी संपत्ति को कथित तौर पर बहुत कम दामों पर ट्रांसफर करके गांधी परिवार की निजी संपत्ति में बदला जा रहा है। जैसे कांग्रेस सरकार देश के ज्यादातर हिस्सों से गायब हो गई, वैसे ही एक दिन वह कर्नाटक से भी गायब हो जाएगी। हर मुमकिन तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है, और यह पक्का किया जाएगा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोग जेल जाएं।

खेल
प्रमुख समाचार

वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने यूएई को 6 विकेट से हराया

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए यूएई को 6 विकेट से हरा दिया। पहले गेंदबाजों ने यूएई को 122/6 पर रोका और फिर 123 रन के लक्ष्य को 13.2 ओवर में हासिल कर ग्रुप स्टेज में लगातार चौथी जीत दर्ज की।

टॉस जीतकर कप्तान एडेन मार्करम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर नमी और बादलों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से दबाव बनाया। कार्बिन बॉश ने शानदार स्पेल डालते हुए 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा कगिसो रबाडा ने भी सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

यूएई की शुरुआत खराब रही। कप्तान मोहम्मद वसीम, आर्यांश शर्मा और सोहैब खान जल्दी आउट हो गए। अलीशन शरफू ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा सहयोग नहीं मिला। निर्धारित 20 ओवर में यूएई 6 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। हल्की बारिश के कारण दूसरी पारी की शुरुआत में थोड़ी देरी हुई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा आक्रामक अंदाज में किया।

एडेन मार्करम और क्विंटन डी कॉक ने सधी हुई शुरुआत दी। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने 36 रन की तेज पारी खेलकर मैच पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। अंत में जेसन स्मिथ ने विजयी रन लेकर टीम को 13.2 ओवर में जीत दिला दी।

इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 से पहले शानदार लय हासिल कर ली है और अब उसकी नजर भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले पर रहेगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 283 अंक चढ़ा निफ्टी 25819 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार (18 फरवरी) को बढ़त में बंद हुए। मेटल और सरकारी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। हालांकि, आईटी शेयरों में लगातार जारी बिकवाली ने बढ़त को सीमित कर दिया। इसके अलावा इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी ने भी बाजार को ऊपर की तरफ खींचा। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 100 से ज्यादा अंक चढ़कर 83,553 पर खुला। लेकिन अंत में 283.29 अंक या 0.34 प्रतिशत की बढ़त लेकर 83,734.25 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 25,752 पर खुला और खुलने के कुछ देर में 25,700 के नीचे फिसल गया। कारोबार के दौरान ज्यादातर समय यह सपाट रहा। लेकिन अंत में 93.95 अंक या 0.37 फीसदी की वृद्धि लेकर 25,819 पर बंद हुआ।

वेनेजुएला के तेल पर मिलने वाली छूट निचले स्तर पर

नईदिल्ली। वेनजुएला के तेल पर भारतीय रिफाइनर्स को मिलने वाली छूट रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों और उद्योग अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय रिफाइनर वेनजुएला के भारी और ज्यादा सल्फर वाले कच्चे तेल ग्रेड पर अब तक की सबसे कम छूट पर सौदे कर रहे हैं। वेनजुएला का मेरे (Merey) कच्चा तेल भारी, हाई सल्फर और एसिडिक किस्म का तेल है। ट्रेडरों के मुताबिक, इस तेल पर मिलने वाली छूट पहली बार 10 डॉलर प्रति बैरल से नीचे चली गई है और यह 6.50 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई है। यह छूट पहले भारतीय रिफाइनरों को मिलने वाली छूट के मुकाबले करीब एक-तिहाई है। यह छूट आईसीई ब्रेंट बेंचमार्क के आधार पर और भारतीय बंदरगाहों तक डिलीवरी के हिसाब से तय की जाती है।

भारत कृत्रिम मेधा नवाचार के प्रमुख केंद्रों में से एक: एनविडिया

नई दिल्ली। भारत अपने मजबूत विकासकर्ता आधार, स्टार्टअप और साझेदार नेटवर्क के दम पर कृत्रिम मेधा (एआई) नवाचार के प्रमुख केंद्रों में शामिल हो गया है। एनविडिया के प्रबंध निदेशक (दक्षिण एशिया) विशाल धूपर ने कहा कि कंपनी देशभर के प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ मिलकर बदलाव को तेज करने और विकास को नई गति देने पर काम कर रही है। धूपर ने कहा कि एनविडिया की विविध साझेदारियां बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कृत्रिम मेधा कोई एकल उत्पाद या एक बार की खोज नहीं है। उन्होंने इसकी पांच परत (लेयर) वाले केक से तुलना करते हुए कहा कि इसके सबसे निचले स्तर पर ऊर्जा, उसके ऊपर चिप, आधारभूत ढांचा, मॉडल और फिर अनुप्रयोग हैं। धूपर ने कहा कि इन सभी परतों का अपना अलग परिवेश है और एनविडिया, भारत के प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ इस पूरी श्रृंखला के हर स्तर पर काम कर रही है।

दिग्गज आईटी स्टॉक पर ब्रोकरेज बुलिश!

नईदिल्ली। आईटी सेक्टर के लिए मौजूदा वित्त वर्ष निराशाजनक साबित हो रहा है। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई तेज गिरावट का असर अब सीधे निफ्टी 50 इंडेक्स में उनके वेटेज पर दिखाई देने लगा है। हालिया गिरावट के चलते आईटी सेक्टर की हिस्सेदारी घटकर 26 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव की चिंता की वजह से भारतीय आईटी सेक्टर में लगातार दबाव देखा जा रहा है। हालांकि, इस स्थिति के बीच ब्रोकरेज हॉउस इन्फोसिस लिमिटेड पर बुलिश नजर आ रहे हैं। कंपनी की एआई रिसर्च और सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी एंथ्रोपिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा से ब्रोक्रेजीज का भरोसा बढ़ा है।

बजट विश्लेषण : स्पीड, स्केल और संकल्प का केंद्रीय बजट

अखिलेश जैन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ना तो छोटा सोचते हैं, ना छोटा करते हैं। स्पीड और स्केल अपने आप में भिन्न होती है। कार्यों के परिणाम भी भिन्न होते हैं। प्रधानमंत्री के लक्ष्य भी भिन्न होते हैं। प्रधानमंत्री कार्य शुरू करके उसको 100% तक पूरा करने का प्रयास करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से देश की सत्ता संभाली है, देश के स्थापित लक्ष्यों को पीछे छोड़ते हुए जिस स्पीड और स्केल से कार्य किया है, रात दिन एक करके बिना विश्राम लिए, वह किसी भी विश्लेषक को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने हमेशा निर्णायक रूप से, अस्पष्टता की जगह काम को, बातों की जगह सुधार को और लोक-लुभावन नीतियों की जगह लोगों को प्राथमिकता दी है।

सन् 2014 में प्रति व्यक्ति की आय 86647 रुपए सालाना थी, 2023 में बढ़कर 172000 रुपए सालाना हो गई, 2026 में लगभग 2.5 लाख से 2.72 लाख रुपए सालाना के बीच तक पहुंचने का अनुमान है, इस बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का भी देश ने सामना किया। कोरोना के बावजूद 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 172000 रुपए सालाना, मतलब लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में, प्रधानमंत्री वैश्विक अनिश्चिताओं, वैश्विक उथल-पुथल, वैश्विक महामारी के बाद भी 172000 रुपए सालाना आय के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे। यही प्रति व्यक्ति आय 2024 - 2025 में 235000 रुपए सालाना तक पहुंच गई। यही प्रधानमंत्री की अर्थनीति, स्पीड और स्केल है, यही मोदी जी का 13 वर्षों का बजट है।

2014-15 में प्रति व्यक्ति जीडीपी 98405 रुपए सालाना के लगभग थी, 2024 - 2025 में प्रति व्यक्ति जीडीपी 234859 रुपए सालाना तक पहुंच गई। यही मोदी जी का 13 वर्षों का बजट है।

भारत का कुल निर्यात 2013-14 के दौरान 465 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर था जो 2024 - 2025 में भारत का कुल निर्यात 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। अर्थात् 11 वर्षों में भारत का निर्यात 177.5 % की दर से सकारात्मक वृद्धि दर को प्राप्त किया। यही मोदी जी का 13 वर्षों का बजट है।

मंदी के दौरान भी भारत ने पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। मोदी सरकार के लगातार सुधारों एवं प्रयासों के परिणाम स्वरूप एफडीआई 2013-14 में लगभग 36 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2024-25 में 80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, 222.23% की दर से सकारात्मक वृद्धि दर को प्राप्त किया। जो निवेशकों के निरंतर विश्वास और सेवा, डिजिटल, विनिर्माण एवं बुनियादी अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निवेश की तेज गति को दर्शाता है। यही प्रधानमंत्री मोदी की अर्थनीति और 13 वर्षों का बजट है।

2014 में हाई- स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 550 किलोमीटर थी, वित्त वर्ष 2025- 2026 में दिसंबर तक 5,364 किलोमीटर हो गई है। लगभग दस गुना बढ़ गई है। यही प्रधानमंत्री मोदी की स्पीड और स्केल है।हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी, 2025 में 164 हो गई है। भारत घरेलू विमानन के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यही प्रधानमंत्री मोदी की अर्थनीति है।नवीकरणीय ऊर्जा तथा संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत मार्च 2014 में 76.38 गीगावॉट पर था, नवंबर 2025 तक 253.96 गीगावाट हो गई, वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले दशक में तीन गुना से अधिक बढ़ गई है। यही प्रधानमंत्री मोदी की अर्थनीति है।

2014 में उच्च गति क्षमता वाली पटरियों की लंबाई 31,445 किमी थी, 2025 तक लगभग दोगुनी से भी ज्यादा होकर होकर 84,244 किमी हो गई है, जिससे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के लगभग 80% हिस्से पर 110 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से परिचालन संभव हो पा रहा है।

जनगणना-2027 राष्ट्र निर्माण की आधारशिला: मुख्यमंत्री साय

सीएम विष्णुदेव ने राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का किया आह्वान

रायपुर। भारत की जनगणना-2027 के सफल संचालन के लिए आयोजित राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। यदि आंकड़े अधूरे या त्रुटिपूर्ण होंगे तो विकास योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित होगा। एक भी व्यक्ति या परिवार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विकास की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है।

उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। यह कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 252 तहसीलों और 19,978 गाँवों में संपन्न किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-गणना की सुविधा से जनभागीदारी बढ़ेगी और जनता का विश्वास ही जनगणना की सफलता का आधार है। यह कार्य विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत-2047 की नींव रखने वाला सिद्ध होगा।

प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित एवं प्रमाणिक संकलन किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों से सभी निर्धारित कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने प्रगणकों के प्रशिक्षण में सपोर्टिव सुपरविजन की तकनीक अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलना चाहिए, जिससे त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो।

उन्होंने नई भवन अनुज्ञाओं को पूर्व से ही ट्रेस करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मकान सूचीकरण के दौरान कोई संरचना छूट न जाए। साथ ही सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में उन्होंने वर्ष 2001 के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चले गए व्यक्तियों की गणना में दोहराव से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना की सफलता सूक्ष्म योजना, समन्वय और सटीक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, इसलिए सभी अधिकारी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ इस राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करे।

इस अवसर पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि जनगणना विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय कार्यों में से एक है। यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है और नीति-निर्माण व विकास योजनाओं की दिशा तय करती है। उन्होंने बताया कि भारत में पहली संगठित जनगणना वर्ष 1872 में प्रारंभ हुई थी और आगामी जनगणना देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी।

उन्होंने कहा कि 150 वर्षों की परंपरा वाली भारतीय जनगणना गाँव, कस्बा और वार्ड स्तर तक प्राथमिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें मकानों की स्थिति, सुविधाएँ, परिसंपत्तियाँ, जनसांख्यिकीय विवरण, धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति, भाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रव्रजन एवं प्रजनन से संबंधित सूक्ष्म एवं विश्वसनीय आँकड़े संकलित किए जाते हैं।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने कलेक्टरों को जनगणना-2027 से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। राज्य स्तरीय संभागायुक्त-कलेक्टर सम्मेलन में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पर्यटन मंत्री वीर बुधु भगत की 234 वीं जयंती में हुए शामिल

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जशपुर जिले के डांडटोली में कोल विद्रोह के महानायक, अमर शहीद वीर बुधु भगत की 234 वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उरांव समाज के लिए निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया तथा उपस्थित जनसमूह को शुभकामनाएं प्रदान कीं।समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि अमर शहीद वीर बुधु भगत ने जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और संगठन शक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास के संरक्षण तथा नई पीढ़ी तक उसके प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत है।

7160 अत्यंत पिछड़े जनजाति घरों को ग्रिड से बिजली देने का लक्ष्य पूर्ण

पीएम जनमन के अमल में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करते हुए देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। इस योजना के तहत विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के 7160 घरों में ग्रिड से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा प्रदेश के ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने हितग्राहियों तथा कंपनी कर्मियों को बधाई प्रेषित की है।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दो वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना की शुरूआत की गई थी जिसे पीएम जनमन के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ की सात विशेष पिछड़ी जनजातियों, अबुझमाड़ियों, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, अगरिया तथा बिरहोर जनजातियों के आवासों का सर्वेक्षण किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 7160 ऐसे आवासों को चिन्हांकित किया गया जहां ग्रिड से बिजली नहीं पहुंची थी। इन घरों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 37 करोड़ रूपये की लागत से अधोसंरचना का विकास किया गया जिसके अंतर्गत टॉवर, लाइन, फीडर, ट्रांसफार्मर आदि की स्थापना की गई और इन्हें क्रियाशील किया गया।

इस तरह छत्तीसगढ,विशेष पिछड़ी जनजातियों के 7160 घरों में बिजली कनेक्शन देने वाला देश का अव्वल राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सबसे कमजोर तबकों को ग्रिड की बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए किये गये कार्यों पर प्रशंसा जाहिर की है। वहीं प्रदेश के ऊर्जा सचिव तथा प्रदेश के छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह तथा काम को अंजाम देने वाले समस्त विद्युत कर्मियों की सराहना की है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के 28 जिलों में अनुसूचित जनजाति बसाहटों तथा इनमें शेष अविद्युतीकृत आवासों में बिजली पहुंचाने के लिए भी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वार्षिकोत्सव छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है: संजय श्रीवास्तव

रायपुर। महंत लक्ष्मीनारायण दास कालेज रायपुरए का वार्षिक उत्सव 18-02-2026 को संपन्न हुआ। इस मौके पर नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उत्सव का शुभारंभ श्री संजय श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। यह उत्सव कॉलेज के छात्रों और विभिन्न विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्रीवास्तव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा ;ह उत्सव सिर्फ एक अवसर नहीं है। बल्कि यह हमारे छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम है। इस प्रकारके आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता और नेतृत्व कौशल को उजागर करने काअवसर मिलता है। छात्रों में नई ऊर्जा का संचार करने और उन्हें अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है।मुख्य अतिथि संजय श्रीवास्तव ने कहा किए ;ह देखना अद्भुत है कि कॉलेज न केवलशिक्षा प्रदान कर रहा हैए बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में भी योगदान दे रहा है।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नेसभी प्रतिभागियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और भविष्य में ऐसे और आयोजनों कीउम्मीद जताई। प्रोफेसर] व्याखाता एवं बड़ी संख्या मे छात्र छात्राएं उपस्थिह रहे।

शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का फायदा हितग्राहियों को समय पर मिले: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों से कहा है कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का फायदा हितग्राहियों को समय पर मिले यह सुनिश्चित हो। इसके लिए पहले से ही हितग्राही से संबंधित जानकारी दुरस्त कर लिया जाये। मुख्य सचिव आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित जनगणना वर्ष 2027 के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में सभी जिलों में पेयजलापूर्ति, गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से पहले से ही लोगों को सावधान रहने एवं बचाव करने जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्ययोजना बनाने और तैयारियां पहले से ही कर लें। कलेक्टर्स को इस वर्ष खरीफ मौसम की धान खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने, राशन दुकानों में खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता, इस साल तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा, जनसमस्याओं के समाधान एवं निवारण, पीएम आवास सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी राशनकार्ड धारकों को पात्रता के अनुसार समय पर खाद्यान्न सामग्री मिले इसके लिए लगातार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की मानीटरिंग करें। मुख्य सचिव ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान संग्रहण केन्द्रों के भौतिक सत्यापन कर धान परिवहन एवं मिलिंग कार्य करने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मिलर्स के लंबित भुगतान करने जरूरी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

सुको ने ग्राम सभा के अधिकारों को सहीं माना: दीपक बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के अंतर्गत गांव की सीमा में प्रवेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में सरकार पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पेसा कानून के तहत ग्राम सभा के अधिकार को सहीं माना है, लेकिन भाजपा सरकार की कृत्यों से स्पष्ट है कि वह नहीं मानती, पांचवी अनुसूची के क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में जहां पर पेसा कानून लागू है, उन क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की सहमति के वनों की कटाई निर्बाध चालू है, कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए जबरिया भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन और पेसा कानून के प्रावधानों के सही क्रियान्वयन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे। सरकार एक तरफ पंचायत विभाग के माध्यम से गांव में प्रवेश को लेकर पेसा के प्रावधान को लेकर तो सहमति जताती है, लेकिन संसाधनों की लूट में उन्हीं ग्राम सभा के आपत्तियों को कुचलकर उनके अधिकार छीनने का काम सरकार खुद ही कर रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय 8 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के नियम लागू किए गए, देवगुड़ी, घोटूल सहित तमाम धार्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन के काम हुए।

शराब दुकान खोलने का निर्णय भाजपा का शराब प्रेम: ठाकुर

रायपुर। नई आबकारी नीति में गाँधी पुण्यतिथि, होली, मुहर्रम के दिन शराब दुकान खोलने के फैसले को भाजपा सरकार का शराब प्रेम करार देते हुये प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार की शराब से राजस्व कमाई की भूख एवं काली कमाई की होड़, शराब कारोबारियों को फायदा पहुँचाने की नीति है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुण्यतिथि के दिन शराब दुकान बन्द कर समाज को नशामुक्ति की प्रेरणा दी जाती है, भाजपा सरकार ने गांधी पुण्यतिथि के दिन शराब दुकान खोलकर बापू की नशामुक्ति के विचारों की हत्या की है। होली एवं मोहर्रम त्यौहार के दिन शराबखोरी को बढ़ावा देकर शांति भंग करने वालो बढ़ावा दे रही है। इससे त्यौहार के दिन नशेड़ी आतंक मचायेंगे, उपद्रव होगा, शांति भंग होगी। वैसे ही प्रदेश लचर कानून व्यवस्था नशा के कारण आपराधिक घटनायें बढ़ी है, महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है। सरकार को महत्वपूर्ण दिन शराब दुकान खोलने के फैसले को वापस लेना चाहिये। भाजपा ने प्रदेश के महिलाओं को सरकार बनने पर शराबबंदी करने का अश्वासन दिया था। महिलाओं के गंगाजल कलश सिर पर रख कर शराबबंदी की मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे।

बजट की राशि खर्च नहीं कर पाना जन विरोधी चरित्र: वर्मा

रायपुर। महत्वपूर्ण मदों में बजट प्रावधान की राशि खर्च नहीं कर पाने पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को धोखा दिया है, केवल घोषणावीर इस सरकार ने बजट को मजाक बना दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल और कृषि से जुड़े आठ विभागों में लगभग 65 हजार करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था लेकिन सरकार की दुर्भावना के चलते केवल 55 हजार करोड़ भी खर्च नहीं हो सके, अर्थात बजट प्रावधान इस सरकार में केवल कागजी आंकड़ा बन कर रह गया है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार में बजट की राशि खर्च नहीं करने के मामले में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति स्वास्थ्य विभाग की है। एक तरफ जहां प्रदेश की आम जनता जांच, इलाज और दवा के अभाव में बे-मौत मर रही है, वही विभाग की अकर्मण्यता के चलते प्रदेश सरकार के बजट प्रावधान का 25 सौ करोड़ खर्च ही नहीं किया गया। कृषि के बजट का 1084 करोड़ यह सरकार खर्च नहीं कर पाई। सड़क, पुल-पुलियों का नव निर्माण तो क्या रखरखाव भी नहीं हो पाया, न ही बजट की राशि का कोई उपयोग कर पाए।

अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही हो : डॉ. महंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में एक आदिवासी ग्रामीण की मृत्यु की जाँच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र लिखकर जाँच की मांग की है।नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में घटित घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं गंभीर है। जिसमें कथित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक आदिवासी ग्रामीण की हत्या की गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पत्र में लिखा कि, जानकारी अनुसार, संबंधित कार्रवाई में नागरिकों की सुरक्षा हेतु नियुक्त अधिकारियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक निर्दोष आदिवासी की मृत्यु हो गई। इस घटना से स्थानीय समुदायों एवं नागरिक समाज में गहरा आक्रोश एवं पीड़ा व्याप्त है तथा प्रशासनिक आचरण, जवाबदेही और मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। उल्लंघन है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। तथ्यों की स्थापना, न्याय सुनिश्चित करने तथा कानून के शासन में जनविश्वास बनाए रखने हेतु एक व्यापक, निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच अत्यंत आवश्यक है।

रायपुर में 20 से 24 फरवरी तक निःशुल्क प्लेसमेंट कैम्प

रायपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायपुर द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 20 फरवरी से 24 फरवरी तक नि:शुल्क प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैम्प टेक्नोटॉस्क बिजनेस साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, मल्टीलेवल पार्किंग, गांधी चौक कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर में प्रतिदिन सवेरे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने के इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपना आवेदन छत्तीसगढ़ रोजगार एप के माध्यम से कर सकते हैं। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति, रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। यह प्लेसमेंट कैम्प पूर्णत: नि:शुल्क है। कैम्प में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां सहभागिता करेंगी। टेक्नोटॉस्क बिजनेस साल्युशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के 400 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं उत्तीर्ण निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 18 हजार रुपए वेतन प्रदान किया जाएगा तथा पदस्थापना रायपुर में होगी। इसी प्रकार आईटीएम एडयूटेक इंडिया लिमिटेड द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव/रिलेशनशिप मैनेजर के 124 पदों पर भर्ती की जाएगी।

शासन की नियमावली के तहत

आरडीए व हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों का होगा हैंडओवर

रायपुर। राज्य शासन के आदेश और प्रस्तावित नियमावली के अनुरूप रायपुर नगर निगम द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) तथा छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के हैंडओवर की कार्यवाही किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शासन स्तर पर आरडीए और हाउसिंग बोर्ड की कुल 9 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और नियमावली जारी होने का अभी इंतजार है। निगम प्रशासन का कहना है कि जैसे ही शासन से स्पष्ट आदेश प्राप्त होंगे, उसी के अनुरूप आगे की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, हैंडओवर की प्रक्रिया से पहले नगर निगम, आरडीए और हाउसिंग बोर्ड संयुक्त रूप से कॉलोनियों का सर्वे करेंगे। इस सर्वे का उद्देश्य कॉलोनियों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना की वास्तविक स्थिति का आंकलन करना होगा। तकनीकी सर्वे में पेयजल आपूर्ति तंत्र, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कों की स्थिति, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, उद्यानों की देखरेख तथा सफाई व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि बिना विस्तृत सर्वे के हैंडओवर लेने से भविष्य में रखरखाव और वित्तीय भार से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रायपुर नगर निगम के नगर निवेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि कई कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में हैं।

विशेष रूप से जलापूर्ति की पाइपलाइन 15 से 20 वर्ष पुरानी बताई जा रही हैं, जिनकी उपयोग अवधि लगभग समाप्ति पर है। इसके अलावा कई स्थानों पर सीवरेज लाइन और नालियां भी क्षतिग्रस्त हैं, जबकि आंतरिक सड़कों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे में हैंडओवर से पहले इन सभी व्यवस्थाओं का सटीक तकनीकी मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि हैंडओवर के बाद इन कॉलोनियों के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम पर आएगी। इसलिए वित्तीय भार, अतिरिक्त स्टॉफ की आवश्यकता और नियमित मेंटेनेंस की रूपरेखा पहले से तय करना जरूरी होगा। यदि कॉलोनियों में अधोसंरचना की स्थिति कमजोर पाई जाती है, तो मरम्मत और उन्नयन के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता भी पड़ सकती है। निगम प्रशासन इस पहलू को गंभीरता से देखते हुए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय करने की बात कर रहा है। निगम प्रशासन का कहना है कि फिलहाल शासन से कोई अद्यतन आदेश या नियमावली प्राप्त नहीं हुई है। हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी तरह शासन के दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।

आवास योजना में फर्जी भुगतान और अधूरे घर के आरोप तथ्यहीन

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर आज 18 फरवरी को प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय जांच दल से विस्तृत भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच रिपोर्ट में कई तथ्य भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी पर आधारित पाए गए हैं। उपायुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश मामलों में भुगतान नियमानुसार हुआ है और निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बागबाहरा जनपद में 12,366 हितग्राहियों की दूसरी किश्त अटकी होने और केवल 25 हजार रुपए पहली किश्त दिए जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि जांच में सामने आया कि योजना शुरू होने से अब तक जनपद पंचायत बागबाहरा में 22,910 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 19,411 मकान पूर्ण हो चुके हैं। शेष 3,499 आवास निर्माणाधीन हैं। प्रशासन के मुताबिक किश्तों का भुगतान निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार किया जा रहा है।

ग्राम तुहामेटा में झुलवती के नाम पर प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत आवास में दो किश्तों में एक लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। जांच में पाया गया कि छत ढलाई का कार्य पूरा है। हितग्राही श्रीमती झूलबती के निधन के बाद उनके पति श्री पीलाराम को उत्तराधिकारी के रूप में पोर्टल में दर्ज किया गया है, जो कि पीएफएमएस में लंबित है।

इसी तरह राजापड़ाव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अडगडी में सुगारो के नाम से वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत है। 40 हजार रुपए की पहली किश्त जारी हो चुकी है। मकान प्लिंथ स्तर पर है और दूसरी किश्त के लिए जियो-टैगिंग पूरी कर ली गई है।ग्राम पंचायत जाड़ापदर में हिरमनी बंजारा के पिता खेतुराम बंजारा के नाम से वर्ष 2024-25 में आवास स्वीकृत है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.